



नई दिल्ली, लखनऊ और रायपुर से प्रकाशित

प्रायोजक

www.dailypioneer.com



भारत ने
अफगानिस्तान
को हराया
स्पोर्ट्स-12

नीट के बाद अब नेट पर बवाल

● छिटपुट घटनाओं का लाखों छात्रों पर असर नहीं पड़ना चाहिए: धर्मद प्रधान

दीपक कुमार झा। नई दिल्ली/पटना

नीट विवाद से जुड़ा रही नरेंद्र मोदी सरकार के लिए बुधवार को यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करना सरकार के लिए गंभीर परेशानी लेकर आया है, जिसने अभी अपना तीसरा कार्यकाल शुरू किया है और अगले सप्ताह संसद का विशेष सत्र निर्धारित है। विपक्षी नेताओं ने गुरुवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर हमला किया और एजेंसी के साथ-साथ केंद्र सरकार पर इन परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के भविष्य को नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह मामला अगले सप्ताह संसद के विशेष सत्र में उठाया जाएगा।

दोनों परीक्षाएं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित की जाती हैं और दोनों प्रवेश परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए थे और इसलिए रद्द करने के कारण उम्मीदवारों, छात्रों, अभिभावकों द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही विपक्षी दलों द्वारा हमले और मुद्दों को



नीट-यूजी और यूजीसी नेट परीक्षा मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते छात्र (बाएं) और नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी।

सुव्यवस्थित करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप भी हो रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा एनईईटी को फिर से आयोजित करने की विपक्ष की मांग के बीच, शिक्षा मंत्री धर्मद प्रधान ने गुरुवार को कहा कि कदाचार की छिटपुट घटनाओं का असर उन लाखों छात्रों पर नहीं पड़ना चाहिए जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास की है। उन्होंने परीक्षण एजेंसी एनटीए के कामकाज को देखने के लिए एक उच्च स्तरीय पैनल की घोषणा की।

देर शाम एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, प्रधान ने विपक्षी दलों से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की अपील की और कहा कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी

(एनटीए) के अधिकारियों सहित दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि एनटीए के कामकाज की समीक्षा और सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति जल्द ही अधिसूचित की जाएगी। जूनियर रिसर्च फेलो, सहायक प्रोफेसर और पीएचडी विद्वानों के चयन के लिए यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने के बारे में प्रधान ने कहा कि परीक्षा का पेपर डाकनेट पर लीक हो गया था।

यूजीसी-नेट रद्द होने के एक दिन बाद, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि परीक्षा के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन छात्रों के हितों की रक्षा के लिए

उनके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई और नए सिरे से परीक्षा की घोषणा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जयसवाल ने कहा कि इनपुट का विवरण साझा नहीं किया जा सकता क्योंकि मामला सीबीआई को भेज दिया गया है और वर्तमान में जांच चल रही है। उन्होंने कहा, कोई शिकायत नहीं मिली लेकिन एजेंसियों से हमें जो जानकारी मिली, उससे संकेत मिलता है कि परीक्षा की शुचिता से समझौता किया गया है। छात्रों के हितों की रक्षा के लिए स्वतः संज्ञान लेते हुए यह कार्रवाई की गई।

जहां कांग्रेस के नेतृत्व वाला

विपक्ष लगातार भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर हमला कर रहा है, वहीं एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने एनईईटी पेपर लीक में राजद का सीधा संबंध होने का आरोप लगाया है क्योंकि मामले की जांच नीतीश कुमार सरकार द्वारा शुरू की गई है। मामले में बिहार पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है, वे फिलहाल पटना जेल में बंद हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दोनों प्रवेश द्वारों में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मनोवैज्ञानिक रूप से ढह गए हैं' और उन्हें इस तरह की सरकार चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा।

पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, यह कहा जा रहा था कि मोदी ने यूक्रेन-रूस युद्ध और इजराइल-गाजा युद्ध रोक दिया, लेकिन वह या तो परीक्षा पेपर लीक को रोकने में सक्षम नहीं हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुभाष त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह सतर्क और संवेदनशील है। उन्होंने कहा, केंद्र प्रतिबद्ध है और लाखों छात्रों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देना... जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी... राहुल गांधी को लाखों छात्रों के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं है। (शेष पेज 9)

बिहार में आरक्षण बढ़ाने का फैसला हाईकोर्ट ने रद्द किया

राजेश कुमार। पटना/नई दिल्ली

बिहार में राजनीतिक दलों को एक बड़ा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय ने गुरुवार को 2023 में बिहार विधानमंडल द्वारा पारित संशोधनों को रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए कोटा 50 से बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। न्यायालय ने पदों और सेवाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) में रिक्रियों के लिए बिहार (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में) आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2023 को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया, जो संविधान और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन है। इस बीच, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने पटना हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता खंड का उल्लंघन है। रिट याचिकाओं को पार्टियों को उनकी लागत का भुगतान करने की अनुमति दी जाती है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बिहार के उपमुख्यमंत्री स्मार्ट चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम



कोर्ट जाणी और बिहार के लोगों को न्याय देगी। उन्होंने कहा, बिहार में, पिछड़े समुदायों, दलितों और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाना चाहिए, इसलिए बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाणी और बिहार के लोगों को न्याय देगी। एकल व्यक्ति, लालू प्रसाद यादव का मतलब आरक्षण विरोधी है, वह अपराध के समर्थक थे। इससे पहले, पटना उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के कोटा में 65 प्रतिशत की बढ़ोतरी को रद्द करने के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया था। उन्होंने कहा, हम आहत हैं और हमें पहले से ही यह संदेह था कि भाजपा आरक्षण को रोकने की कोशिश करेगी। हमने चुनाव के दौरान पहले ही कहा था कि बीजेपी वाले आरक्षण के खिलाफ हैं। आपको पता ही होगा कि जब हमने जाति आधारित सर्वे कराया तो बीजेपी के लोगों ने इसे रोकने के लिए जनहित याचिका दायर की, लेकिन अंत में हमारी जीत हुई। मुझे समझ नहीं आता कि सीएम इस पर चुप क्यों हैं। आदेश में कहा गया है, राज्य ने आरक्षण प्रतिशत में वृद्धि प्रदान करने से पहले कोई हाइल अध्ययन या विश्लेषण का प्रयास नहीं किया, यह रिपोर्ट से स्थापित है। यह कि राज्य विभिन्न श्रेणियों की जनसंख्या के मात्र अनुपात पर आगे बढ़ा, जबकि सरकारी सेवाओं और शैक्षणिक (शेष पेज 9)

केजरीवाल को शराब नीति केस में जमानत

राजेश कुमार। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए राउज एव्यू कोर्ट ने गुरुवार को उन्हें दिल्ली आबकारी शुल्क नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। अवकाश न्यायाधीश न्याय बिंदू ने केजरीवाल और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दो दिनों तक सुनवाई के बाद आदेश पारित किया। केजरीवाल के शुक्रवार को जेल से बाहर आने की संभावना है। विशेष न्यायाधीश ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने आदेश पारित करते हुए कहा, आरोपी को एक लाख रुपये की राशि पर जमानत दी जाती है। जमानत बांड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जाएगा। हालांकि, अदालत ने आप नेता को राहत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें लगाईं, जिनमें यह भी शामिल है कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। न्यायाधीश ने केजरीवाल को जरूरत पड़ने पर अदालत में पेश होने और जांच में सहयोग करने का भी निर्देश दिया।

आप नेता आतिशी ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर 'सत्यमेव जयते' कहकर प्रतिक्रिया



व्यक्त की। आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य को हराया नहीं जा सकता, केवल परेशान किया जा सकता है। अदालत ने केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाते की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका भी खारिज कर दी है। ईडी के विशेष वकील जोहब हुसैन ने जांच एजेंसी द्वारा अपने कानूनी उपायों का इस्तेमाल करने तक आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की। हालांकि, अदालत ने रोक के अनुरोध को खारिज कर दिया।

इससे पहले दिन में, विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदू ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें केजरीवाल को अपराध की कथित आय और सह-अभियुक्तों से जोड़ने की मांग की गई थी और बचाव पक्ष ने दावा किया था कि

अभियोजन पक्ष के पास इसे खत्म करने के लिए कोई सबूत नहीं है। अदालत ने मामले में बुधवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत तीन जुलाई तक बढ़ा दी थी। बस के दौरान, ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर, 2021 को केजरीवाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह ने किया था, जिन पर टीटीय राज्य में आप के फंड का प्रबंधन करने का आरोप है।

ईडी ने कोर्ट को बताया कि होटल को दो किस्तों में 1 लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसका भुगतान चनप्रीत सिंह (सह-अभियुक्त) ने अपने बैंक खाते से किया था। चनप्रीत वह व्यक्ति है जिसने विभिन्न अंग्रेजिया से 45 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। अंग्रेजिया प्रणाली एक पुरानी समानांतर बैंकिंग प्रणाली है जहां व्यापारी एक विश्वसनीय कूरियर के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में नकदी भेजते हैं। यह आम तौर पर मुंबई और गुजरात में आभूषण व्यवसाय में प्रचलित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश एएसबी एक्सवी राजू ने कहा कि सह आरोपी चनप्रीत सिंह ने उद्यमियों से भारी नकद राशि प्राप्त की और अरविंद केजरीवाल के होटल में उतरने के बिलों का भुगतान किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि (शेष पेज 9)

तमिलनाडु में जहरीली शराब से 39 लोगों ने गंवाई जान

कुमार चेलप्पन। चेन्नई

मंगलवार की कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में मरने वालों की संख्या गुरुवार शाम तक 39 तक पहुंच गई और जहरीली शराब पीने वाले 100 से अधिक लोगों को जिले के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इन अस्पतालों के डॉक्टरों के अनुसार, मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अस्पतालों में भर्ती कराए गए कई लोगों की हालत कथित तौर पर गंभीर है। यह सब मंगलवार रात को चेन्नई से 250 किमी दक्षिण में जिले के करुणपुरम गांव में शुरू हुआ, जब लोगों ने जहरीली शराब पीना शुरू कर दिया और उल्टी करने लगे। जिन लोगों को अस्पतालों ले जाया गया उनमें से कुछ ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही अंतिम सांस ले ली। तमिलनाडु में जहरीली शराब के सेवन से होने वाली मौतें कोई नई बात नहीं है क्योंकि लोग शराब तस्करो से सामान खरीदना पसंद करते हैं, जिनके पास पूरे राज्य में गुप्त दुकानों का एक नेटवर्क है, जहां अरक का निर्माण और बिक्री कानून द्वारा प्रतिबंधित है।

ऐसी रिपोर्टों के बाद कि संबंधित अधिकारियों ने जिले में बड़े पैमाने पर जहरीली शराब की बिक्री के बारे में लोगों की शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने

जिला कलेक्टर को हटा दिया और जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्वाचित करने का आदेश दिया। स्टालिन ने पीड़ितों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये और अस्पताल में इलाज करा रहे लोगों को 50,000 रुपये देने की भी घोषणा की। शराब त्रासदी के कारणों की जांच के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। आयोग को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय सुझाने को कहा गया है। इस दुर्घटना में जो बात सामने आती है वह यह है कि केवल समाज के सबसे गरीब तबके के लोगों को जान गई है। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एडुपानी पलानीस्वामी ने तमिलनाडु सरकार से मृतकों के लिए मुआवजा राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने का आग्रह किया। पलानीस्वामी ने कहा कि उनकी पार्टी, अन्नाद्रमुक, उन बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिन्होंने त्रासदी में अपने माता-पिता दोनों को खो दिया है और उन्होंने द्रमुक सरकार पर जहरीली शराब की व्यापक बिक्री और खपत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनकी पार्टी के विधायक की अपील को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। (शेष पेज 9)

सेबी ने रेलिगेयर को बर्मन परिवार की खुली पेशकश के लिए विनियामक अनुमोदन लेने का आदेश दिया

पीटीआई। नई दिल्ली

बाजार नियामक सेबी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) रेलिगेयर एंटरप्राइजेज (आईएल) को आदेश दिया है कि वह डायर इंडिया के प्रवर्तक बर्मन परिवार की खुली पेशकश के लिए 12 जुलाई से पहले विनियामक प्राधिकरणों से वैधानिक मंजूरी ले। बर्मन समूह ने रेलिगेयर के निदेशक मंडल और उसकी चेयरपर्सन रश्मि सलूजा पर खुली पेशकश में बाधा डालने का आरोप लगाया। इस बीच, रेलिगेयर ने तर्क दिया कि बर्मन परिवार अधिग्रहण के लिए उपयुक्त और योग्य नहीं है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने कहा कि एनबीएफसी ने कोई सबूत नहीं दिखाया कि बर्मन समूह ऐसी कथित कमजोरियों से प्रस्त है। खुली पेशकश को रोकने के बोर्ड के प्रयास पर असंतोष जताते हुए सेबी ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि रेलिगेयर ने स्पष्टतः शत्रुतापूर्ण तरीके से काम किया है। सेबी ने रेलिगेयर को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इडका) और सेबी के पास अनुमोदन के लिए आवेदन करने का आदेश दिया है। इस संबंध में प्रतिक्रिया देते हुए रेलिगेयर के प्रवक्ता ने कहा, सेबी के (शेष पेज 9)



प्रचंड गर्मी से राहत पाने के लिए हर प्रयास कर रहे लोग।

फाइल फोटो

दिल्ली में गर्मी से मौतों का सिलसिला जारी

सौम्या शुक्ला। नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी में प्रचंड गर्मी की चपेट में आने के साथ मृत्यु दर में वृद्धि देखी जा रही है। शहर में अत्यधिक गर्मी के कारण क्योंकि लगभग 210 अधिक लोगों को जान चली गई है, जिनमें से 192 बेघर लोग शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पतालों में गर्मी से संबंधित बीमारियों के कारण कुल 22 मौतें दर्ज की गईं। इसके अलावा, बेघरों के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठन सेंट्र फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट (सीएचडी) ने दावा किया कि 11 से 19 जून तक दिल्ली में गर्मी की लहर के कारण 192 बेघर लोगों की मौत दर्ज की गई, जो पिछले साल की तुलना में 156 प्रतिशत की भारी वृद्धि है, उस दौरान 75 लोगों ने जान गंवाई थी। हल्की बारिश और अधिकतम तापमान में गिरावट के रूप में कुछ राहत के बावजूद दिल्ली पिछले कुछ दिनों से बढ़ते न्यूनतम तापमान के साथ भीषण गर्मी की स्थिति से जूझ रही है। सफदरजंग अस्पताल के अधिकारियों के अनुसार गर्मी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित 33 मरीजों को भर्ती कराया गया था। इनमें से 13 की मौत पिछले 24 घंटों में हुई। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि आरएमएल अस्पताल में पिछले 24 घंटों में संधिहृत् हीटस्ट्रोक के 22 मरीज आए, जिनमें से चार की मौत हो गई।

इस बीच, शहर के मुख्य श्मशान, निगमबोध घाट पर, दाह संस्कार की संख्या में वृद्धि देखी गई है। हालांकि, अधिकारी इस बात को पुष्टि नहीं कर सकते कि क्या मौतें हीट स्ट्रोक से संबंधित थीं। निगमबोध घाट संचालन समिति के महासचिव सुमान गुप्ता ने कहा, बुधवार को निगमबोध घाट पर 142 लाशें अंतिम संस्कार के लिए लाई गईं, जो 50-60 शवों के दैनिक औसत से लगभग 136 प्रतिशत अधिक है। मंगलवार को भी यह संख्या अधिक थी जब शहर के सबसे पुराने और सबसे बड़े श्मशान घाट पर 97 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। गुप्ता ने कहा, आम तौर पर, लगभग 50-60 शव दाह संस्कार के लिए प्रतिदिन यहां लाए जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में यह संख्या अधिक हो गई है। आज, सुबह से 35 दाह संस्कार हो चुके हैं और दिन के अंत तक यह संख्या बढ़ सकती है। इसके अलावा, पिछले 48 घंटों के दौरान दिल्ली के आसपास चर्चित सामाजिक-आर्थिक प्रभुत्व के 50 लोगों के शिव बरामद किए गए। हालांकि, पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों ने इसकी पुष्टि नहीं की है कि इन सभी की मौत गर्मी से संबंधित कारणों से हुई है या नहीं। मामले को संज्ञान लेते हुए, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के प्रधान सचिव आशीष कुंद्रा ने मुख्य सचिव को राष्ट्रीय राजधानी में ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर सक्सेना की पीड़ा के बारे में बताया। सक्सेना ने निर्देश दिया कि समाज कल्याण विभाग, डीयूएसआईबी और स्वास्थ्य के संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि (शेष पेज 9)

मर्तुहरि महताब लोस के अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त पावनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सात बार के सांसद मर्तुहरि महताब को बृहस्पतिवार को लोकसभा का अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिज्जू ने यह जानकारी दी। रिज्जू ने कहा कि कटक से भाजपा सांसद महताब को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होने तक पीठासीन अधिकारी के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 95 (1) के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अस्थाई अध्यक्ष (प्रोटेम) नियुक्त किया गया है। अठारहवीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य अस्थाई अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेंगे। रिज्जू ने बताया कि अस्थाई लोकसभा अध्यक्ष की सहायता पीठासीन (शेष पेज 9)

दुश्मनों को सबक सिखाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे: मोदी

● अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेने के लिए श्रीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को घोषणा की कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। श्रीनगर में चंपावरिंग यूथ, ट्रांसफॉर्मिंग जेड्स कार्यक्रम में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र

सरकार ने हाल के आतंकी हमलों को बहुत गंभीरता से लिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम जम्मू-कश्मीर के दुश्मनों को सबक सिखाने में संकोच नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर के लोग स्थानीय स्तर पर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजते हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है? इसलिए अब इसकी तैयारी है। वह समय दूर नहीं जब आप अपने वोटों से जम्मू-कश्मीर की नई सरकार चुनेंगे। वह दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू-कश्मीर एक बार फिर एक राज्य के रूप में अपना भविष्य बेहतर बनाएगा।



जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हुए

प्रधानमंत्री ने 12 अप्रैल को उधमपुर में एक चुनाव प्रचार रैली के दौरान इसी तरह की घोषणा की थी।

हाल के चुनावों में रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख करते हुए, प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र में जम्मू-कश्मीर के लोगों

पैसा देते ही कैसे मिल रहे पानी के टैंकर : सचदेवा

जल संकट आप जिम्मेदारी से भागती है चाहे दिल्ली सरकार हो या फिर निगम : हर्ष

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जल संकट को लेकर प्रदेश भाजपा ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह दुखद है कि पिछले 10 साल से दिल्ली सरकार की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार के चलते जहाँ दिल्ली का विकास ठप रहा है तो वहीं आज लोग विशेषकर गरीब अपना रोजमर्रा का काम धंधा छोड़ कर एक-एक बाल्टी पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि आप सरकार की शह पर पानी की चोरी और बर्बादी हो रही है और केजरीवाल सरकार पानी चोरी करकर सीनाजोरी कर रही है। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि दिल्ली सरकार लगातार भ्रम फैला रही है कि हरियाणा दिल्ली को पूरा पानी नहीं दे रहा है और हिमाचल प्रदेश से मिल सकने वाले अतिरिक्त जल को भी बाधित कर रहा है जो सब एक झूठ है, तथ्यों से बहुत दूर है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केन्द्रीय राज्य मंत्री मल्होत्रा, सांसद मनोज तिवारी, रामवीर सिंह बिधूड़ी, योगेंद्र चंदोलिया, बाँसुरी स्वराज ने बृहस्पतिवार को संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में कहा कि केजरीवाल सरकार की झूठी बयानबाजी के बाद भाजपा नेताओं ने हरियाणा सरकार के मुख्य मंत्री नयब सिंह सैनी से बात की तो जो तथ्यात्मक आंकड़े एवं जानकारी सामने आई उसे मीडिया से साझा की। साथ ही कहा कि हरियाणा से पानी सप्लाई को लेकर झूठे भ्रमात्मक प्रचार के लिए वे दिल्ली सरकार को आलोचना की।

उन्होंने कहा कि दो वर्ष पूर्व तक जब जब दिल्ली सरकार पानी चोरी एवं बर्बादी रोकने में अपनी असफलता के चलते गर्मियों में पूरा पानी देने में विफल रही है तो हरियाणा एवं पंजाब पर दोष मढ़ती रही पर इस वर्ष केवल हरियाणा पर दोष मढ़ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उससे अतिरिक्त पानी ना मांग कर हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त जल मांग रही है जो केवल एक राजनीतिक नोटकी है।

भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि अगर जल संकट है और पानी की कमी है तो पैसा देते ही हर नुककड़ पर पानी



प्रस वार्ता के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ में मंत्री हर्ष मल्होत्रा व सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, मनोज तिवारी, बाँसुरी स्वराज।

टैंकर और पानी के 20 लीटर कैन धड़ल्ले से कैसे मिल रहे हैं। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि दिल्ली में जल की कोई कमी नहीं है बल्कि केजरीवाल सरकार उपलब्ध जल को काला बाजारी करवा रही है।

सचदेवा ने केन्द्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा एवं अन्य सांसदों की मौजूदगी में हरियाणा सरकार से प्राप्त तथ्यों को सार्वजनिक किया। उन्होंने वर्ष 2018 में भी केजरीवाल सरकार ने इसी तरह हरियाणा एवं पंजाब राज्यों पर दिल्ली को पूरा जल ना देने के आरोप लगाये थे। आरोप लगाती केजरीवाल सरकार अपर यमुना रिवर बोर्ड के समक्ष गई और जांच के बाद यमुना बोर्ड ने फैसला दिया कि दिल्ली सरकार का आरोप झूठ है और हरियाणा दिल्ली को संबोधित समझौते अनुसार पूरा जल सप्लाई कर रहा है।

वर्ष 2021 में फिर जल संकट पर पड़ोसी राज्य हरियाणा दोषारोपण किया और फिर इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय को ले गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित समिति ने जांच की और रिपोर्ट आई कि हरियाणा समझौता अनुसार पूरा पानी दे रहा है। सचदेवा ने कहा कि इस वर्ष अप्रैल से ही जल की कमी सामने आने लगी और भाजपा ने मामले की जांच कर पाया कि ना हरियाणा से आने वाले कच्चे पानी की

आतिशी का आमरण अनशन आज से : संजय

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि भाजपा, केंद्र व हरियाणा सरकार से दिल्ली के हक का पानी देने की गुहार लगाकर थक चुकीं जल मंत्री आतिशी शुक्रवार से अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे। सिंह ने इस मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन इंडिया से समर्थन देने की गुहार लगाई है।

संजय सिंह ने बृहस्पतिवार को संवाददाता सम्मेलन में जल संकट के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, वे प्रदर्शन और नाटकबाजी करते हैं। अगर वे वास्तव में चाहते हैं कि दिल्ली को पानी मिले

तो उन्हें हरियाणा भवन के बाहर प्रदर्शन करना चाहिए। जल मंत्री आतिशी भाजपा शासित राज्य हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का पानी लेने के लिए 21 जून से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगी। उन्होंने कहा, वह इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस के घटक दलों से अपील करते हैं कि वे इस लड़ाई में उनका साथ दें। हम हरियाणा से अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं।

कमी है ना ही शुद्ध किये पेयजल की। इसके बाद भी चारों तरफ पानी के लिए हाहाकार है। मैं 2024 के अंत तक भाजपा ने स्थापित कर दिया कि पाइप लाइन से लीकेज एवं सरकार द्वारा संरक्षित जल टैंकर्स माफिया की लूट जल समस्या के लिए केजरीवाल सरकार जिम्मेदार है। 16 जून को दिल्ली सरकार की अर्जी पर अपर, यमुना रिवर बोर्ड को 62वें ओचक

बैठक हुई जिसकी सुनवाई 9 जून तक चली और पूरी जांच के बाद यमुना बोर्ड ने फैसला सुनाया कि दिल्ली को आज भी हरियाणा से समझौता कोटा 924 क्यूसेक से कहीं अधिक 1050 क्यूसेक पानी मिल रहा। मनोज तिवारी ने कहा कि पानी की किल्लत पिछले कई दिनों से है तो उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाया गया।

सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर आप नेताओं ने कहा, सत्यमेव जयते

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है।

मंत्री आतिशी ने खुशी जाहिर की और कहा सत्यमेव जयते। राज्यसभा सांसद डॉ. संदीप पाठक ने ट्वीट कर कहा कि जाको राखे साइडों मारि न सके कोय। बाल न बाँका करि सके जो जग बैरी होय। राघव चड्ढा ने कहा सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। न्याय की जीत है सच्चाई की जीत है। आतिशी ने एक्स पर कहा सत्यमेव जयते तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता, केवल परेशान किया जा सकता है। पार्टी ने एक्स पर कहा, सत्य परेशान हो सकता है,



आतिशी



संदीप पाठक



राघव चड्ढा

पराजित नहीं किया जा सकता। भाजपा की ईडी की तमाम आपत्तियों को खारिज करते हुए न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री

अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी है। अदालत ने आप नेता को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर गृह्त दी।

अदालत ने 48 घंटे के लिए आदेश पर रोक लगाने के ईडी के अनुरोध को भी खारिज कर दिया। इस तरह वह एक बार फिर जेल से बाहर आ जाएंगे। इससे पहले पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए अंतरिम जमानत दी थी।

पानी की कमी केवल आंतरिक कुप्रबंधन का कारण : डॉ. यादव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

हरियाणा के सिंचाई एवं जल संसाधन राज्य डॉ अमय सिंह यादव ने दिल्ली सरकार के आरोपों को नकारते हुए स्पष्ट किया है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हिस्से का पूरा पानी दे रहा है।

राजधानी में पानी की किल्लत केवल दिल्ली को आंतरिक खराब व्यवस्था के कारण है। हरियाणा पानी पर राजनीति नहीं करता अर्थात् हम पानी को पानी की आवश्यकता के रूप में देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी को पानी मिले यह सबकी जिम्मेदारी है। हरियाणा दिल्ली को पानी देने में कोई कमी नहीं कर रहा है। मंत्री ने दावा

किया कि निर्धारित 719 क्यूसेक से अधिक 1050 क्यूसेक पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा है।

डॉ अमय सिंह यादव ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में संवाददाता सम्मेलन में आंकड़ों के साथ हरियाणा द्वारा दिल्ली को दिए जा रहे जलापूर्ति की जानकारी दी। इस अवसर पर सिंचाई विभाग के आयुक्त एवं सचिव पंकज अग्रवाल, ईआईसी वीरेंद्र सिंह, अधीक्षक अभियंता वाईडब्ल्यूएस दिल्ली तरुण अग्रवाल व एक्सईएस दिल्ली मंजीत सिंह भी उपस्थित थे। सिंचाई राज्य मंत्री ने कहा कि पानी को लेकर दिल्ली सरकार राजनीतिक नोटकी कर रही है। समय-समय पर अलग-अलग एजेंसियों की ओर से

बोले, दिल्ली सरकार के हरियाणा पर कम पानी देने के आरोप निराधार और तथ्यों से परे

बार-बार सत्यापन किया गया है। हरियाणा द्वारा दिया गया डाटा सही पाया गया है। एक भी एजेंसी यह नहीं कह सकती कि हरियाणा ने पानी कम दिया है। दिल्ली सरकार अपने कुप्रबंधन को ठीक करने की बजाय बार-बार हरियाणा पर आरोप लगा रही है। हरियाणा नियमित रूप से पानी की पूर्ण अधिकृत हिस्सेदारी की आपूर्ति कर रहा है। मुनक हेड दिल्ली के लिए 1050 क्यूसेक पानी लगातार छोड़ रहा है और दिल्ली संपर्क बिंदु बवाना प्लांट पर यूवाईआरबी द्वारा तय 924 क्यूसेक से अधिक पानी दिया जा रहा है।

एनएसयूआई का शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन

नीट-नेट परीक्षा में कथित अनियमितता का मामला तूल पकड़ा, छात्रों ने की नारेबाजी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नीट-नेट परीक्षा में कथित अनियमितता का मामला तूल पकड़ लिया है। मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर नकली नोटों के साथ विरोध प्रदर्शन।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और नीट-यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच की भी मांग की। पुलिस ने एनएसयूआई नेताओं और कार्यकर्ताओं को



पुलिस ने हिरासत में लिया है। बाद में उन्हें छोड़ दिया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में प्रधान के आवास के बाहर अन्य छात्रों ने प्रदर्शन किया। नीट और नेट परीक्षा में कथित

घोटाले के खिलाफ अपने विरोध को दर्शाने के लिए नकली नोट हवा में उछाले। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) पर प्रतिबंध लगाने और पेपर लीक की कथित घटनाओं की जांच की मांग की।

नीट और नेट में अनियमितता के दोषियों पर हो कार्रवाई : एबीवीपी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अनियमितता के चलते यूजीसी नेट की परीक्षा रह होने के साथ ही देश भर के छात्रों में संदेह, भ्रम एवं निराशा फैल गई है। इस वर्ष पीएचडी के प्रवेश भी यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर होने हैं।

अभ्यर्थियों में अचानक असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस संबंध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिक्षा मंत्रालय से इस संबंध में त्वरित निर्णय लेकर स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है ताकि छात्रों का समय और भविष्य संकट में नहीं आए। एबीवीपी

के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा, परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की घटनाएं विचलित करने वाली एवं दुष्भावपूर्ण हैं जो न केवल एनटीए जैसी परीक्षा एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है बल्कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली हैं। यह स्थिति किसी भी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। इसी क्रम में बीते दिन यूजीसी नेट की परीक्षा का रद्द होना, यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों के साथ-साथ पीएचडी प्रवेश की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य भी अधर में डालने वाला है।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर दिल्ली वाले करेंगे 21 आसनों का प्रदर्शन

निगम के सभी जोनल कार्यालयों तथा स्कूलों में योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली नगर निगम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निगम विद्यालय पुष्प विहार सेक्टर-1 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन कर रहा है। योग की इस अद्भुत धारा में नगर निगम शिक्षा विभाग के 150 विद्यार्थी, अध्यापिकाएँ एवं निगम कर्मचारी प्रतिभागिता करेंगे एवं 21 योग आसन का अभ्यास करेंगे।

दिल्ली नगर निगम शिक्षा विभाग के विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी छात्र भी इसमें अपनी प्रतिभागिता उपस्थित करायेंगे। भारत सरकार द्वारा निर्देशित प्रोटोकॉल के अंतर्गत विभिन्न आसन जैसे ताडुसन, वृक्षासन, भद्रासन, कपालभाती, आदि 21 आसनों का सुंदर प्रदर्शन किया जायेगा। प्रातः 7:30 बजे से प्रारम्भ यह प्रक्रिया प्रातः 08:50 बजे अपने अंतिम चरण पर पहुँचेंगी।

इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारी भाग लेंगे और इस दौरान दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों और वार्डों में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। इस



एनडीएमसी के आठ स्थानों पर योग

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) द्वारा शुक्रवार को सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक 8 प्रमुख स्थानों पर स्वयं और समाज के लिए योग की थीम पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 मनाया जा रहा है।

1. नेहरू पार्क-चाणक्यपुरी,
2. लोधी गार्डन - गेट नंबर 1 से प्रवेश,
3. तालकटोरा गार्डन - गेट नंबर 1 से प्रवेश,
4. कर्तव्य पथ - लॉन के दक्षिण की ओर,
5. आईएसएस आवासीय परिसर - न्यू मोती बाग,
6. संजय झील - लक्ष्मी बाई नगर,
7. सिंगापुर पार्क - शांति पथ पर सिंगापुर दूतावास के पास

मार्च 2025 तक सभी 383 गांवों में पहुंचेगी पीएनजी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी के कुल 383 गांवों में से 311 गांवों को इस वर्ष दिसंबर तक पाइपड नेचुरल गैस कनेक्शन से लैस कर दिया जाएगा, जबकि शेष 72 गांवों को मार्च 2025 तक इस सुविधा से संपन्न कर दिया जाएगा।

गांवों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, जो राजधानी के सभी गांवों की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल ही में गांवों में पीएनजी आपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की। उन्हें बताया गया कि अब तक 111 गांवों

एलजी ने कार्य प्रगति की समीक्षा की

में पीएनजी सुविधा उपलब्ध कराई गई है और इस वर्ष दिसंबर तक 200 गांवों को पीएनजी से लैस कर दिया जाएगा। शेष 72 गांवों को मार्च 2025 तक पीएनजी की आपूर्ति शुरू हो जाएगी।

उपराज्यपाल को आईजीएल अधिकारियों द्वारा बताया गया कि 111 गांवों में पीएनजी आपूर्ति से 1.79 लाख परिवारों को लाभ होगा। आईजीएल को अब तक इसके लिए 1.29 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं।

टिल्लू ताजपुरिया गैंग का निशानेबाज गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद रोहिणी से टिल्लू ताजपुरिया को गिरफ्तार किया है। इस निशानेबाज की पहचान सुमित के रूप में हुई है। कंडावला पुलिस थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में सुमित पैरोल मिलने के बाद भाग गया था। इसके साथ ही अलीपुर पुलिस थाने में दर्ज हत्या के एक और मामले में वह वांछित है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, रोहिणी पुलिस के विशेष दल के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया को पिछले साल तिहाड़ जेल के अंदर प्रतिद्वंद्वी गिरोहों के सदस्यों ने कथित तौर पर पीट-पीटकर मार डाला था।

पीएम मोदी की जीत पर सांसदों का स्वागत

केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, सांसद योगेंद्र चंदोलिया का रोहिणी में सम्मान

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भाजपा के कार्यकर्ताओं ने रोहिणी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा विधायक विजेन्द्र गुप्ता के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुए लोक सभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैट्रिक जीत पर भव्य आयोजन किया।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और निर्वाचित सांसद योगेंद्र चंदोलिया का रोहिणी में स्वागत किया। उन्होंने विशेष रूप से रोहिणी विधानसभा के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने



कार्यक्रम में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और सांसद योगेंद्र चंदोलिया का स्वागत करते विजेन्द्र गुप्ता।

की जीत में उनके समर्पण और प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मल्होत्रा ने कांग्रेस और आप बेमेल गठबंधन के बावजूद बीजेपी की जीत की सराहना की।

उन्होंने योगेंद्र चंदोलिया ने दिल्ली में सबसे अधिक अंतर से जीतने के लिए मनादाताओं का दिल से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से रोहिणी विधानसभा के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने

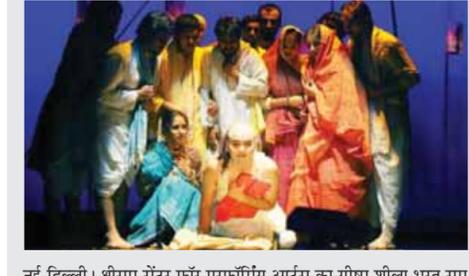
संक्षिप्त समाचार

पावरग्रिड शीर्ष 30 की सूची में शामिल



नई दिल्ली। पावरग्रिड की कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशंस टीम को रेपुटेशन टुडे द्वारा लगातार चौथी बार भारत की 30 शीर्ष कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशंस टीमों की सूची में शामिल किया गया है। पावरग्रिड की टीम ने अंशुमन टंडन, सीजीएम (कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशंस) के नेतृत्व में रवि कुमार, डीजीएम (कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशंस) और अक्षत चोपड़ा, सहायक प्रबंधक (कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशंस) के साथ एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्राप्त किया। इस वर्ष इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला पावरग्रिड एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। शीर्ष कॉर्पोरेट कम्प्यूनिकेशंस टीमों की सूची में शामिल करने के लिए एक जूरी ने स्वतंत्र रूप से शीर्ष 30 टीमों का मूल्यांकन किया। रेपुटेशन टुडे ने एशिया पैसेफिक कम्प्यूनिकेशंस एंड पब्लिक रिलेशन्स डायरेक्टर्स (एपीएसीडी) के साक्षात्कारी की, जिन्होंने कर्पणियों का मूल्यांकन करने के लिए भारत से दो, सिंगापुर से एक और मध्य पूर्व से एक कुल चार चैंप्टर अध्यक्षों को आमंत्रित किया।

एम.के. रैना निर्देशित नाटक महाबली का मंचन



नई दिल्ली। श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स का ग्रीष्म शीला भरत राम थियेटर फेस्टिवल शुरू हुआ। 23 जून तक चलने वाले इस 5 दिवसीय थियेटर फेस्टिवल की शुरुआत स्व. गिरीश कर्नाड के नाटक 'अग्नि और बरखा' के मंचन के साथ हुई। फेस्टिवल के दूसरे दिन, गुरुवार को अस्मर वजाहत द्वारा लिखित एवम् निर्देशक एम.के. रैना द्वारा निर्देशित नाटक महाबली का मंचन हुआ। महाबली नाटक गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। महाकवि तुलसीदास अपने समय के एक 'विद्रोही' और 'प्रगतिशील' कवि थे जिन्होंने एक महान रचना की, जिसने उस समय के समाज को बहुत प्रभावित किया। श्री राम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के एक्जीक्यूटिव वाइस प्रेजिडेंट हेमंत भरत राम ने कहा हमारा उद्देश्य उम्दा नाटक, अभिनय और मानवीय संवेदनाओं के विभिन्न रंग प्रस्तुत करने का रहता है जो दर्शकों का मनोरंजन करें।

गरीब रथ एक्सप्रेस जुलाई से फिर होगी शुरु

नई दिल्ली। पूर्वोत्तर सीमा रेलवे ने गरीब रथ एक्सप्रेस की दो जोड़ी सेवाओं को जुलाई से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। ये ट्रेनें अगरतला-कोलकाता तथा गुवाहाटी-कोलकाता के बीच अपने संबंधित गंतव्यों के लिए निर्धारित दिनों पर चलेंगी। ट्रेन संख्या 12502 (अगरतला-कोलकाता) गरीब रथ एक्सप्रेस 3 जुलाई, 2024 से प्रत्येक बुधवार को चलेगी। ट्रेन संख्या 12518 (गुवाहाटी-कोलकाता) गरीब रथ एक्सप्रेस 6 जुलाई से प्रत्येक शनिवार को चलेगी।

मंदिर की जमीन कब्जा रहे दबंग: महंत योगी सेवानाथ का आरोप, शिकायत करने के बाद भी पुलिस नहीं कर रही दबंगों पर कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

सेक्टर-42 स्थित डीएलएफ फेज-5 में गोल्फ कोर्स के पास महाभारत कालीन अस्थल मंदिर और कुछ वर्ष पहले यहां बनाई गई गौशाला की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वे इस क्षेत्र में नशे का काम भी करते हैं। यह आरोप लगाया है मंदिर के महंत योगी सेवानाथ ने।

यहां सिविल लाइन में पत्रकारों से बात करते हुए महंत योगी सेवानाथ ने सुशांत लोक फेज-1 पुलिस थाना में दी शिकायत की प्रति साक्षात् करते हुए कहा कि वे इस मंदिर में पिछले 35 साल से रह रहे हैं। मंदिर व गौशाला का संचालन कर रहे हैं। वजीरवादा गांव के छह नामजद लोगों के खिलाफ शिकायत में भी उन्होंने कहा है कि ये सभी झगड़ालू व माफिया प्रवृत्ति के हैं। पिछले कुछ दिनों से ये लोग नशीले पदार्थों का सेवन करके मंदिर में आ रहे हैं। मंदिर



पत्रकारों से बात करते महंत योगी सेवानाथ।

व गौशाला के संचालन में दखल दे रहे हैं। गौशाला से जबरदस्ती दूध ले जाकर बाहर बेच रहे हैं। उनके द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आरोप है कि इन दबंगों ने मंदिर के एक कमरे पर कब्जा करके एक परिवार को रखा हुआ है। वह इनके साथी का परिवार है। आरोपी मंदिर

से दक्षिणा के पैसे भी उठा ले जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वे 31 मार्च 2024 को आरती कर रहे थे तो उसके सेवक जयपाल को घंटी बजाने के लिए इन दबंगों ने मंदिर के एक कमरे पर कब्जा आए और जयपाल को घंटी बजाने से रोका। उसे धमकी भी दी। महंत योगी सेवानाथ ने बताया कि जब वे झगड़ा सुनकर बाहर आए तो उनके साथ भी झगड़ा किया गया। उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। डरकर उन्होंने डायल 112 पर कॉल की। महंत ने बताया कि उन्हें, उनकी शिष्या संतोष नाथ व सेवक जयपाल को लगातार परेशान किया जा रहा है। पुलिस को भी उन्होंने इस बाबत शिकायत दी है।

यह जमीन नगर निगम की है: एसएसआई ज्ञानेन्द्र

इस मामले में थाना सुशांत लोक के सहायक उप-निरीक्षक ज्ञानेन्द्र ने बताया कि यह जमीन नगर निगम गुरुग्राम की है। कोर्ट से भी नगर निगम के पक्ष में निर्णय आ चुका है। यह नगर निगम का अधिकार है वह कब अपनी जमीन पर कब्जा ले। इसमें कोई ऐसा ऑफेंस नहीं बनता, जिसमें पुलिस कार्रवाई करे। इनकी फाइल को क्लॉज कर दिया गया है।

नाथ ने बताया कि जब वे झगड़ा सुनकर बाहर आए तो उनके साथ भी झगड़ा किया गया। उन्हें भी जान से मारने की धमकी दी। डरकर उन्होंने डायल 112 पर कॉल की। महंत ने बताया कि उन्हें, उनकी शिष्या संतोष नाथ व सेवक जयपाल को लगातार परेशान किया जा रहा है। पुलिस को भी उन्होंने इस बाबत शिकायत दी है।

विदेशों में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली पांच युवतियों समेत आठ गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

लोगों को कॉल करके विदेशों में नौकरी दिलाने का दिलासा दिया जाता था। वह दिलासा नहीं झांसा होता था। इस झांसे में युवा फंसकर लाखों रुपये गंवा देते थे। ऐसे ठगी करने वाले गिरोह और फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मौके से 5 युवतियों समेत 8 साइबर ठगों को पकड़ा गया है। सहायक पुलिस सुवहाना विपिन अहलावत ने गुरुवार को बताया कि आरोपियों से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं।

जानकारी के अनुसार इंटरनेशनल जॉब सोल्यूशन डॉट कॉम के नाम से वेबसाइट बनाकर युवाओं को नौकरी दिलाने की बात कही जाती थी। वह भी विदेशों में। ज्यादातर बेरोजगार युवा इनके झांसे में आ जाते थे। ये साइबर ठग युवाओं को विश्वास में लेकर धोखाधड़ी एवं ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर प्रति युवा 2 से 3 लाख रुपये लेते थे। ठगी हुई राशि को भी ये साइबर ठग फर्जी बैंक खाते में डलवाते थे, ताकि आराम से उस राशि को निकालकर पुलिस कार्रवाई से बच सकें। फर्जी बैंक खाते इनका अन्य साथी इनको उपलब्ध करवाता था। आरोपी कारीब 6 महीने से कॉल सेंटर चलाकर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ठगी करने के लिए इन लोगों को प्रतिमाह 18 हजार रुपए की सैलरी मिलती थी।

पुलिस टीम द्वारा इस फर्जी कॉल सेंटर से 4 लड़कियों समेत 8 आरोपियों को काबू किया। जिनकी पहचान नरेंद्र कुमार निवासी गांव पालम दिल्ली, विक्रान्त सिंह निवासी बारा खुर्द जौड़, रवि कुमार निवासी रघुवीर एनक्लेव दिल्ली, काजल निवासी अलीगंज कोटला मुबारकपुर दिल्ली, गरिमा निवासी जयानपुर जिला आजमगढ़ (उप्र), एगनेश प्रानेश निवासी निवासी मधु-प्रदेश (मध्य-प्रदेश), रंजन कुमार निवासी श्याम विहार फेज-2 दिल्ली व साहित पूनिया निवासी गांव डिकानिया गंगानगर (राजस्थान) के रूप में हुई। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्यवाही करते हुए थाना साइबर अपराध दक्षिण में धारा केस दर्ज किया गया।



गुरुग्राम पुलिस द्वारा विदेशों में नौकरी दिलाने के नाम पर पकड़े गए साइबर ठग।

फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़

● हर्बल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नाम पर करते थे ठगी, 4 युवतियों समेत 11 धरे

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

डिजिटलीकरण के दौर में हमारे काम जितने सरल हुए हैं, उतना ही रिस्क भी बढ़ा है। इससे साइबर ठगी की घटनाएं भी बढ़ी हैं। यहां ऑनलाइन हर्बल सेक्वुअल दवाइयों बेचने के नाम पर पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। गुरुवार को सहायक पुलिस आयुक्त सोहना विपिन अहलावत ने जानकारी दी कि पुलिस टीम द्वारा कॉल सेंटर से 4 लड़कियों सहित कुल 11 आरोपियों को काबू किया।

पुलिस के अनुसार थाना साइबर पूर्व प्रबंधक निरीक्षक सविन कुमार की पुलिस टीम ने तकनीक की सहायता से सेक्टर-18 में इस कॉल सेंटर को पकड़ा। मौके से पकड़े गए आरोपियों की पहचान श्याम दुबे निवासी गांव जोड़ा जिला मुरैना (मध्य-प्रदेश), आदर्श कुमार सिंह निवासी अंबेडकर कॉलोनी वसंत विहार, दिल्ली, कुशल रोहिल्ला निवासी खेड़ला, गुरुग्राम, पिपुषु चौहान निवासी गांव बिजोरी जिला बदायूं (उत्तर-प्रदेश), विवेक चोपड़ा निवासी एनआईटी फरीदाबाद, गुलशन



पुलिस द्वारा हर्बल दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के नाम पर फर्जी कॉल सेंटर से गिरफ्तार ठग।

कुमार निवासी गांव दहीबड़ा गोपालगंज (बिहार), राजकुमार निवासी गांव डेरा महारौली दिल्ली, पूजा चौहान निवासी शिव कॉलोनी, झोटवाड़ा जयपुर (राजस्थान), भावना निवासी भिवानी, आनामिका राजावत निवासी ग्वालियर (मध्य-प्रदेश) व प्रिया शर्मा निवासी देव अपार्टमेंट महिपालपुर, दिल्ली के रूप में हुई।

पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के खिलाफ आगामी कार्यवाही करते हुए थाना साइबर अपराध पूर्व में नियमानुसार अभियोग अंकित करके आरोपियों अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिछले करीब 1 वर्ष से उपरोक्त प्रकार से ठगी करने की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ठगी की वारदातों को अंजाम देने के लिए आरोपियों को 15 हजार रुपए की सैलरी तथा ठगी गई राशि का 5 प्रतिशत हिस्सा मिलता था। आरोपियों द्वारा ठगी में प्रयोग किए जा रहे 7 मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स व 2 सीपीयू भी बरामद किए गए हैं।

आईटीआई में प्लेसमेंट के लिए 26 को लगेगा रोजगार मेला

● विभिन्न क्षेत्रों की सात कंपनियों 375 छात्रों का करेगी चयन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) गुरुग्राम द्वारा 26 जून को अप्रेंटिस व प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें हरियाणा निवासी कोई भी आईटीआई पास विद्यार्थी भाग ले सकता है।

रोजगार मेले में सात विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों भाग ले रही हैं जो अपने नियम व शर्तों के हिसाब से 375 विद्यार्थियों का चयन करेगी।

कादिदान ने कहा की मेले में भाग लेने के इच्छुक किसी भी प्रतिभागी को इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो संस्थान में आकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक अपने एनएसी व पीएनएसी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए हैं वे किसी भी कार्य दिवस पर संस्थान के शिक्षता शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य जयदीप सिंह कादिदान ने बताया कि कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग हरियाणा के निदेशक द्वारा

जारी निर्देशानुसार 26 जून को आईटीआई गुरुग्राम के प्रांगण में अप्रेंटिस व प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें हरियाणा निवासी कोई भी आईटीआई पास विद्यार्थी भाग ले सकता है।

रोजगार मेले में सात विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियों भाग ले रही हैं जो अपने नियम व शर्तों के हिसाब से 375 विद्यार्थियों का चयन करेगी।

कादिदान ने कहा की मेले में भाग लेने के इच्छुक किसी भी प्रतिभागी को इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो संस्थान में आकर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन छात्र छात्राओं ने अभी तक अपने एनएसी व पीएनएसी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए हैं वे किसी भी कार्य दिवस पर संस्थान के शिक्षता शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

गरीब-जरूरतमंदों को सशक्त बनाने का काम कर रहे सीएम सैनी: वोहरा

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार शपथ लेते ही पहला फैसला अन्नदाता को सम्मान निधि जारी करने और 3 करोड़ गरीब परिवारों को घर देने का ऐलान कर दिया। उसी तरह पिछले 10 वर्षों से प्रदेश की जनता को सशक्त करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार लगातार योजनाएं लागू कर जनता को मजबूत करने का काम कर रही हैं।

लोकसभा चुनाव के लिए लगी आचार संहिता हटते ही मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी ने महात्मा गांधी गरीब बस्ती योजना के तहत 100-100 गज के प्लॉट, सूर्य घर मुपत्त बिजली योजना, बिजली बिल से मंथली मिनिमम चार्ज हटाना, हरियाणा अन्त्येदय परिवार परिवहन योजना आदि अनेकों योजनाओं को शुरू कर प्रदेश की जनता को सशक्त करने का काम किया है। भाजपा जिला कार्यालय अटल कमल पर



पार्टी कार्यालय में बैठक करते भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार वोहरा।

आयोजित संगठनात्मक बैठक में भाजपा जिला अध्यक्ष राज कुमार वोहरा ने यह कहा। बैठक में जिला अध्यक्ष राजकुमार वोहरा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, संगठन की कार्य पद्धति, कार्य योजना आदि संगठनात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा की और संगठन के आगामी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर शक्ति केन्द्रों पर योग शिविर आयोजित किये जाएंगे।

योग सिर्फ कसरत नहीं, जीवन जीने का एक तरीका है: रितु कटारिया

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

मिसेज हरियाणा-2018 एवं समाजसेविका रितु कटारिया ने कहा कि भारतीय योग पद्धति का आज पूरी दुनिया में डका बज रहा है। बिना कोई दवा किए योग के जरिये हम स्वस्थ रह सकते हैं। योग सिर्फ एक कसरत नहीं, यह जीवन जीने का तरीका है। योग को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। यह बात उन्होंने गुरुवार को यहां गुरुग्राम नेचुरोपैथी क्वोर सेंटर (जीएनसीसी) में आयोजित योग शिविर में कही। जीएनसीसी नेचुरोपैथी में योग शिविर का आयोजन जीएनसीसी की निदेशक डॉ. सुनीता कटारिया व सुनील कटारिया की ओर से किया गया।



प्राणायाम शिविर में योग करती मुख्य अतिथि व अन्य।

इस अवसर पर डॉ. उषा आर्य द्वारा अग्निहोत्र हवन और योग, प्राणायाम सत्र योगाचार्य आर.के. अग्रवाल द्वारा किया गया। योग, प्राणायाम सत्र में रितु कटारिया ने कहा कि योग के जरिये हम

विकास में अग्रणी बनेगा पृथला: नयनपाल

● विधायक ने गांव हीरापुर में किया 60 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने कहा है कि लोकसभा चुनावों के बाद क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है और जो विकास कार्य आचार संहिता के कारण रुक गए थे, उन्हें फिर से नई गति से शुरू कर दिया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि विधानसभा चुनावों से पूर्व पृथला



नारियल फोड़कर विकास कार्यों का शुभारंभ करते विधायक नयन पाल रावत।

क्षेत्र विकास के मामले में फरीदाबाद अब नई अपितु हरियाणा का सबसे अग्रणी क्षेत्र बनकर उभरेगा। रावत एचआरडीएफ स्कीम के तहत गांव हीरापुर में बनाए गए 44 लाख के विभिन्न रास्तों का उद्घाटन तथा करीब 16 लाख से बनकर तैयार होने वाले

रास्ते का शिलान्यास करने के उपरान्त उपस्थित ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान विकास कार्यों का शुभारंभ करने पर ग्रामीणों ने विधायक नयनपाल रावत का सम्मान रुपी पगड़ी पहनाकर एवं फूल मालाओं से स्वागत किया।

हाईवे की जमीन खाली करने को माइक से दी चेतावनी

पायनियर समाचार सेवा। पलवल

नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया के निर्देश पर बघौला में हाईवे की भूमि पर अतिक्रमण किए लोगों के खिलाफ जल्द अभियान चलाया जाएगा। इस मामले में पलवल डीसी की ओर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाने के बाद हाईवे की टीमों ने बघौला में माइक से गुरुवार को एक बार फिर से सूचना देकर लोगों हाईवे की जमीन खाली करने को कहा है। अधिकांश ग्रामीण अपने निर्माणों को पहले ही हटा चुके हैं।

हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया ने उच्चाधिकारियों ने बताया कि घटना प्रबंधन टीमों के माध्यम से हाईवे की

भूमि पर बने दुकानों और दुकानों की जमीन को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए हाईवे की टीमों ने बघौला में जमीन कब्जाने वालों को माइक से सूचना देकर हाईवे की जमीन खाली करने को कहा है। अधिकांश ग्रामीण अपने निर्माणों को पहले ही हटा चुके हैं।

स्वच्छता तैयार, जल्द खुलेगा वृद्ध सेवा आश्रम

● वृद्ध आश्रम संचालन के लिए आगे आवेदन

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

बुजुर्गों को बेहतर माहौल में आवासीय सेवा उपलब्ध कराने में जिला प्रशासन सक्रिय रूप से अपना दायित्व निभा रहा है। जरूरतमंद बुजुर्गों को राहत पहुंचाने के लिए संचालन करने की रूपरेखा तैयार की है। यह बात गुरुवार को जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने ही। उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की महानिदेशक आशिमा बराड़ को जिला में क्रियान्वित विभागीय योजना से



वृद्ध सेवा आश्रम संचालन के महेनजर बैठक लेते डीसी निशांत कुमार।

अवगत कराया। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जानकारी दी कि सामाजिक न्याय, अधिकारिता अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्येदय (सेवा) विभाग द्वारा वृद्ध सेवा आश्रम संचालन करने के लिए प्रस्ताव 30 जून तक आमंत्रित किए जा रहे हैं। समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना के लिए मापदंड

निर्धारित किए गए हैं। सेवा भाव के साथ कार्य करने वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना के तहत हरियाणा सरकार के स्वामित्व वाली इमारत में वृद्धाश्रम का संचालन होगा है। ऐसे में जिला सेक्टर-4 में रेडिंग्स सोसायटी द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं।

संक्षिप्त समाचार



कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड के शपथ ग्रहण समारोह में महिला सदस्य को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते कैनविन के संस्थापक डा. डीपी गोयल व नवीन गोयल।

‘कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड समाज को दे रही नई दिशा’ गुरुग्राम। कैनविन फाउंडेशन की ओर से वीवार कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में सच्चा साथी ब्रिगेड से जुड़े समाजसेवियों को समाजसेवा की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कैनविन फाउंडेशन के संस्थापक डा. डी.पी. गोयल व सह-संस्थापक नवीन गोयल ने शिरकत की। उन्होंने कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड के क्रियकलापों को भी साझा किया। कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड के सदस्य गुरुग्राम के अलग-अलग क्षेत्र में किसी को भी मेडिकल संबंधी कोई जरूरत हो, या फिर संस्था की कोई भी सेवाएं चल रही हैं, उनके प्रति जागरूक करेंगे लोगों को मदद करेंगे। समाज में जागरूकता लेकर आएंगे। इसी उद्देश्य से इसका गठन किया गया है। डा. डी.पी. गोयल ने कहा कि कैनविन फाउंडेशन समाज में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। सभी के सहयोग से संस्था निरंतर समाज हित में कदम बढ़ा रही है। कैनविन फाउंडेशन के तहत कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड भी संचालित की जा रही है। इसमें समाज में सेवा करने वाले लोगों को शामिल करके सभी के साझा प्रयासों से समाज सेवा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति समाज सेवा में आना चाहता है, वह सच्चा साथी ब्रिगेड में सदस्य बनकर काम करे।

आईटीआई छात्र को जमकर पीटा, घायल

पलवल। पुरानी रॉजिश के चलते आईटीआई छात्र के साथ गेट पर मारपीट कर घायल करने का मामला प्रकाश में आया है। घायल हालत में छात्र को अस्पताल में दाखिल कराया गया। मामले में कैप थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। गांव टीकरी ब्राह्मण निवासी अमन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह आईटीआई पलवल में पढ़ता है। वह गांव में आईटीआई जाने के लिए आटो में बैठा और वहां पहुंचा। जब वह आईटीआई के गेट पर पहुंचा तो वहां कशिश अनुभव अभयराज अरुण महेंद्र देवीलाल गोयल कुलदीप देवेन्द्र दीपक सहित करीब 11 लड़के जिनके हाथों में हथियार थे। उक्त लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उसके दोस्त रजत ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसके साथ भी मारपीट की। इस हमले में दोनों घायल हो गए और हमलावरों से बचकर अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचे यहां भी उन्होंने हमला कर दिया। पीड़िता ने हमले की सूचना पुलिस को दी तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। हमलावर पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए।

ट्रेन में महिला से लूटपाट, चार लाख के जेवर व कैश लूटा

पलवल। जीआरपी थाना अंतर्गत पलवल असावटी स्टेशन के बीच बांद्रा एक्सप्रेस ट्रेन में बैठी एक महिला से लूटपाट करने का मामला प्रकाश में आया है। वारदात के समय ट्रेन आउटर पर खड़ी हुई थी। आरोपी महिला से उसका बैग लूटकर फरार हो गया जिसमें महिला के चार लाख रुपए के जेवर और कैश था। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र हीरापदानी इस्टेट निवासी ने पुलिस को उभेद गोयल ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह अपने दो बच्चों के साथ मुंबई जाने के लिए जालंधर रेलवे स्टेशन से बांद्रा एक्सप्रेस में बैठी। इसी दौरान जब ट्रेन पलवल असावटी स्टेशन के बीच पहुंची तो गाड़ी अचानक आउटर पर रुक गई। तभी एक अनजान युवक उसके पीछे आकर खडा हो गया और उसके पर्स को लेकर फरार हो गया। पर्स में उसके चार लाख के जेवर और कैश था। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है।

नीट परीक्षा समग्र जांच

नीट परीक्षा पर उठे सवाल को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने वर्तमान परीक्षा में प्रशासनिक त्रुटियों की जांच का आदेश दिया है। नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नॉलॉजी (नीट) परीक्षा भारत में चिकित्सा व दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में स्नातक स्तर पर भारतीयों का प्रवेश द्वार है, लेकिन वर्तमान समय में यह विवादों में घिर गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा संचालन में संभावित लापरवाही पर चिन्ता प्रकट करते हुए व्यापक जांच के आदेश दिए हैं। 4 जून को परिणामों की घोषणा के बाद से ही 'नीट' परीक्षा विभिन्न मुद्दों के कारण विवादों में घिर गई है। इनमें प्रश्न पत्र में गलतियाँ, ग्रेस मार्क्स का गलत आबंटन तथा पेपर लीक व धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं। इस कारण छात्र और उनके माता-पिता पुनः परीक्षा की मांग कर रहे हैं। हालाँकि, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी-एनटीई के अधिकारियों ने पेपर लीक से इनकार किया, पर इसके बावजूद शिक्षा मंत्री धर्मनंदा प्रधान ने स्वीकार किया है कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर 'कुछ अनियमितताएँ' सामने आई हैं। पूरे देश में चिकित्सा प्रवेश को मानक बनाने के लिए 'नीट' को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विभिन्न चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश का एक आधार बनाना था। लेकिन इसकी शुरुआत से ही परीक्षाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनमें धोखाधड़ी के आरोप, प्रश्न पत्र लीक तथा असमान पहुँच की शिकायतें शामिल हैं। इसके कारण परीक्षा के पक्ष-विरुद्ध में व्यापक बहस तथा विरोध प्रदर्शन हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने एक प्रमुख निर्णय में 'नीट' परीक्षा के प्रशासन पर उठते गंभीर सवालों पर ध्यान दिया था। उसने संभावित लापरवाही को



रेखांकित करते हुए व्यापक जांच का आदेश दिया। पिछले वर्षों में 'नीट' प्रश्न पत्र लीक व धोखाधड़ी के अनेक मामलों में घिरी रही। इसके कारण न केवल परीक्षा की शुचित्वा प्रभावित हुई, बल्कि इससे परीक्षा करवाने वाले अधिकारियों की निष्ठा भी संदेह के घेरे में आ गई। ऐसे मुद्दे एक निरंतर समस्या बन गए हैं जिसके कारण व्यवस्था में विश्वास घटा है तथा जनता में निराशा बढ़ी है। इसके साथ ही परीक्षा तक पहुँच तथा समानता पर भी सवाल उठे हैं। आरोप है कि 'नीट' मूलतः शहरी क्षेत्रों के समृद्ध छात्रों पर ध्यान केंद्रित करती है जिनकी पहुँच उच्च गुणवत्ता वाली कोचिंगों तथा शिक्षा संसाधनों तक होती है। इससे ग्रामीण व आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों को नुकसान उठाना पड़ता है। इस असमानता के कारण अनेक राज्यों तथा समुदायों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं क्योंकि वे स्वयं को वर्तमान व्यवस्था में हाशियाकृत मानते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संभावित लापरवाही के कारण जांच का आदेश 'नीट' परीक्षा प्रक्रिया में प्रशासनिक कमियों की गंभीरता उजागर करता है। परीक्षा बोर्डों के भीतर या संबंधित उद्यमों में भ्रष्टाचार के आरोप हैं जिनके कारण पेपर लीक होते हैं या रिश्वत के बदले छात्रों को धोखाधड़ी की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार का आंतरिक भ्रष्टाचार परीक्षा की निष्ठा गहराई तक प्रभावित करता है। कुछ राज्यों ने क्षेत्रीय व भाषाई भिन्नताओं के कारण अपने छात्रों को होने वाले नुकसान के कारण 'नीट' का विरोध किया है। इस विरोध के पीछे व्यापक राजनीतिक कारण हो सकते हैं जहाँ कुछ राजनीतिक हित चिकित्सा प्रवेश परीक्षाओं के केंद्रीकरण के खिलाफ हैं। वास्तव में 'नीट' प्रक्रिया में विश्वास बहाल करने के लिए जांच तथा यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि भावी चिकित्सा छात्रों को न्यायोचित अवसर मिलें।



भारत की सनातन परंपरा है योग

योग का भारत की सनातन परंपरा में अर्थ जोड़ है। इसका दूसरा अर्थ मनः समाधि अर्थात् मानसिक स्थिरता प्राप्त करने से है। दूरगामी दृष्टि से देखने पर लगता है कि योग ब्रह्मांड से स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में है।



डा. विकास नैटियाल
(लेखक, इतिहास के प्रोफेसर हैं)

स्वामी रामदेव जैसे योग गुरुओं एवं सरकार के प्रयासों से योग भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर असाधारण रूप से लोकप्रिय हो रहा है। योग का भारत की सनातन परंपरा में सामान्य अर्थ जोड़ से है तथा दूसरा अर्थ मनः समाधि अर्थात् मानसिक स्थिरता प्राप्त करने से है। दूरगामी दृष्टि से देखने पर लगता है कि योग ब्रह्मांड से स्वयं का सामंजस्य स्थापित करने के संबंध में है। भारतीय चिंतन पद्धति में योग का जनक पतंजलि को माना जाता है किंतु योग एक सनातन प्रक्रिया रही है। पतंजलि से पूर्व भी भारतीय इतिहास एवं संस्कृति में योग का उल्लेख आता है। भारतीय चिंतन के प्राचीनतम छोर पर सांख्य दर्शन के जनक कपिल मुनि का नाम एक सिद्धयोगी के रूप में मिलता है। श्रीमद्भगवत गीता के रचयिता ने भी योगेश्वर श्रीकृष्ण के मुख से यही कहलवाया है कि सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, मानो कपिल के समान कभी किसी और को योग सिद्ध हुआ ही न हो किंतु कपिल की ऐतिहासिकता को लेकर मतारंभ रहे हैं।

योग का ऐतिहासिक प्रारंभ आज से 5000 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप की सिंधु-सरस्वती सभ्यता की आदि योगी (प्रोटो शिव) की मुहर में देखा जाना अधिक उपयुक्त लगता है। पशुपति शिव कही जाने वाली इस मुहर में एक योगी भद्रासन की शांभवी मुद्रा में विराजमान है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त शांभवी मुद्रा के योगी की इस मुहर को सर्वप्रथम पुरातत्वविद जाँन मार्शल द्वारा शिव से जोड़ते हुए इस सील को प्रोटो शिव कहा गया।

वर्तमान में अनेक विद्वान इस योगी की मुहर में जो कुछ भी अंकन हुआ है, उसे ऋग्वेद के रुद्र (शिव) से संबंधित मंत्रों से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। इन विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद के रुद्र संबंधी कुछ मंत्रों में उन्हीं पशुओं-हाथी, बाघ, गंडा, भैंसा, हिरण का उल्लेख हुआ है जो सिंधु सभ्यता में पशुपति की मुहर में अंकित हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि



इस सभ्यता के लोग मोटे तौर पर शांतिप्रिय थे। जिसका कारण संभवतः योगिक प्रवृत्तियों की भूमिका रही होगी। भारतीय उपमहाद्वीप की इस सभ्यता में योग की इन गहन स्थितियों को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि योग इस सभ्यता की समयावधि (2500 ईसा पूर्व) से पहले ही भारतीय सभ्यता में विद्यमान रहा होगा।

वैदिक कालीन संस्कृति की ऐतिहासिकता अनेक इतिहासकारों द्वारा 1500 ईसा पूर्व से बताई जाती है किंतु श्रुति परंपरा को अगर गहराई से देखा जाए तो वैदिक संस्कृति इससे कई सौ वर्ष पूर्व की रही होगी। ऋग्वेद का ऋषि प्रकृति से सीधे संवाद करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ मन की एकाग्रता के द्वारा प्रकृति के साथ योग करने का प्रयास किया गया है। ऋग्वेद की सबसे अधिक चर्चित ऋचा गायत्री मंत्र है। इस मंत्र में भीमहि शब्दावली का प्रयोग है जिसका अर्थ है ध्यान करें। इस मंत्र में सूर्य के सावित्र रूप (सविता) का ध्यान करने का वर्णन आया है न कि सावित्री की पूजा करने, प्रार्थना करने, नमस्कार करने का उल्लेख आया है। यहाँ सविता से तात्पर्य सूर्य के साथ साथ सृजनात्मकता से भी है। वस्तुतः योग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयोग व्यक्ति की चेतना को जागृत कर उसे नवीन के सृजन करने योग्य बनाया जा सकता है।

योग का ऐतिहासिक प्रारंभ आज से पांच हजार वर्ष पूर्व भारतीय उप-महाद्वीप की सिंधु-सरस्वती सभ्यता की आदियोगी, यानी भगवान शंकर की मुहर में देखा जाना अधिक उपयुक्त लगता है। पशुपति शिव कही जाने वाली इस मुहर में भगवान शंकर भद्रासन की शांभवी योग मुद्रा में विराजमान हैं।

बौद्ध एवं जैन आंदोलनों में भी योगिक क्रियाओं का विस्तार देखा जा सकता है। गौतम बुद्ध का संपर्क अरण्य संस्कृति के दो योगियों आलार कालाम एवं उदक रामपुत्र से हुआ किंतु अपने खोज पूर्ण न हो पाने के कारण वे अंतिम सत्य को पाने के लिए पञ्चानन में बैठकर साधना करने लगे। बुद्धत्व की प्राप्ति के उपरांत वे एक

ही आसन में 7 दिन तक बैठे रहे एवं मुक्ति का आनंद लेते रहे। इस स्थिति को पतंजलि के योग में आनंदानुगतसमाधि कहा गया है। उनके द्वारा प्रारंभ की गई प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान पर आधारित ध्यान की विधि विपश्यना वर्तमान में भी प्रचलन में है। संभवतः महात्मा बुद्ध की विचारधारा भारतीय सनातन के इतिहास में अथात्य के मार्ग से विज्ञान तक की एक अद्वितीय यात्रा रही।

पर्वतों काल में योग एवं ध्यान की तकनीक पर आधारित बौद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शाखा योगाचार का विकास हुआ। जैन पंथ के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव (आदिनाथ) का स्वयं एक सिद्धपुरुष होने का उल्लेख आता है। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकरों के नाम के साथ इंदियों का स्वामी नाथ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। यहाँ इनकी हठ योगियों के नाथ के साथ सीमित समानता भी दिखाई देती है।

भारतीय सनातन परंपरा में कहा गया है कि युद्ध जीतने से अधिक महत्वपूर्ण स्वयं को जीतना है। योगिक परंपरा की दृष्टि से जैन तीर्थंकरों द्वारा सुखासन के स्थान पर ताडुसन, पर्वतासन, कायोत्सर्ग आसन का प्रयोग किया गया है। संभवतः पतंजलि ने भी जैन धर्म में यम नियमों के पहचान कर उन्हें महत्त्व बताया। ऐतिहासिक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है

कि पतंजलि की योग सूत्र पर भारत की बौद्ध एवं जैन जैसी श्रमण विचारधाराओं का भी प्रभाव रहा। कालांतर में व्यास द्वारा योगसूत्र पर एक भाष्य लिखा गया। आठवीं शताब्दी में कश्मीर के प्रत्यभिज्ञा दर्शन की परंपरा के अंतर्गत विज्ञान भैरव नामक एक शैव दर्शन का ग्रंथ लिखा गया। इस ग्रंथ में ध्यान लगाने के 112 उपायों का उल्लेख मिलता है। पूर्व मध्यकाल में भारतीय इतिहास में योगिनी संप्रदाय, गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय, हठयोग का विकास होता हुआ दिखाई देता है। ब्रह्म संबंधी चिंतन एवं यू की परंपरा कबीर एवं अन्य निर्गुण संत में देखी जा सकती है।

इन्हीं परंपराओं ने कबीर को एक क्रांतिकारी सुधारक एवं युगावतार के रूप में विकसित किया। योग की इस परंपरा का प्रभाव सूफियों कश्मीर के कृषि संप्रदाय, चिश्ती एवं कादरी पर भी देखा जा सकता है। 17 वीं शताब्दी में चेरंड मुनि द्वारा योग विषय पर चेरंड संहिता लिखी गई एवं इस ग्रंथ में 84 आसनों का विस्तृत विवेचन मिलता है। इसके उपरांत योगी पायाहरि बाबा के शिष्य योगी जैत राम द्वारा 18 वीं शताब्दी में योगासनमाला नामक ग्रंथ में योग के आसनों का उल्लेख मिलता है। जिसमें 110 आसनों का रेखा चित्रों के साथ वर्णन मिलता है। भारतीय योग परंपरा का प्रभाव तिब्बत की संस्कृति में भी देखा जाता है।

तिब्बती लामाओं द्वारा ध्यान के माध्यम से शरीर पर नियंत्रण रखने के अद्भुत प्रमाण दिखाई देते। यहाँ के भिक्षु वर्षों तक ध्यान मुद्रा में रहा करते थे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक भारत में अंग्रेजी राज्य का राजनीतिक रूप से ही नहीं अपितु अन्य रूपों से भी प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। पश्चिम साम्राज्यवाद की चुनौतियों के प्रत्युत्तर में स्वामी रामकृष्ण एवं अन्य सिद्धों द्वारा अपनी साधना का विकास किया गया।

उन्हीं के परमशिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा वेदांत के चिंतन के आधार पर भक्ति योग कर्म योग राजयोग का पहली बार आधुनिक काल में वैज्ञानिक विवेचन किया गया। आज भारत के प्रयासों से योग को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हो चुकी है वर्तमान समय में उम्मीद की जाती है कि योग के माध्यम से वैश्विक रूप से मानव जीवन को आने वाले समय में अधिक शांत एवं समृद्ध बनाया जा सकेगा।

मोदी सरकार की विदेश नीति

भू-राजनीतिक तनावों के बीच मोदी की जी 7 में सहभागिता लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करती है।



कुमार चेलपन
(लेखक, द पायनियर के विशेष संवाददाता हैं)

भू राजनीतिक तनावों के बीच मोदी की जी 7 में सहभागिता लोकतांत्रिक सिद्धान्तों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता प्रकट करती है। इससे विश्व मंच पर उसकी स्थिति भी स्पष्ट होती है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने के एक सप्ताह के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। उन्होंने इस सप्ताह इटली में राष्ट्रों के शक्तिशाली समूह जी 7 के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सम्मेलन में पधार अग्रणी व अरब देशों के अनेक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें कर मुख्यतः अमेरिकन व यूरोपीय नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया। तीसरी बार उल्लेखनीय रूप से पद

प्राप्त करने के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की पहली विदेश यात्रा थी। लगभग दो महीने चले चुनाव में अत्यधिक भयानक गर्मी के बीच लगभग 670 मिलियन मतदाताओं ने मतदान में प्रतीक्षा की ताकि वे सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता चुन सकें। हालाँकि, महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी अपने दम पर बहुमत प्राप्त करने में विफल रही और वह अब नेतृत्व के लिए चुनाव-पूर्व गठबंधन वाले राजनेताओं के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। यह ऐसे समय महत्वपूर्ण है जब यूरोप के अनेक हिस्सों के साथ अमेरिका में लोकतांत्रिक उथलपुथल व्याप्त है।

अमेरिका में इस साल के अंत में चुनाव होंगे और वहाँ दोनों पक्षों की ओर से बहस तीखी होती जा रही है। इसी प्रकार यूरोपीय संसद के चुनावों में धुर-दक्षिणपंथी पार्टियाँ आगे आ रही हैं जिसका प्रभाव लंबे समय तक भू-राजनीति पर पड़ेगा। मोदी को इस तथ्य से संतोष है कि उनको पश्चिमी देशों के समक्ष भारतीय लोकतंत्र की स्थिति स्पष्ट



करने के लिए सावधानी से चुने राजनयिक बयानों पर निर्भर नहीं होना पड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में पश्चिमी देशों की अमेरिका में भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के बारे में अनेक सवाल उठे थे जिनमें अल्पसंख्यक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रताओं तथा प्रेस की स्वतंत्रता, आदि शामिल थे। भारतीय मतदाताओं द्वारा लगभग पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनना इस बात का प्रमाण है कि पार्टी पर समुचित नियंत्रण एवं

संतुलन लागू होंगे। इसमें सर्वोच्च पदों पर लोगों की नजर रहेगी तथा संसद में जीवन्त विपक्ष की उपस्थिति प्रधानमंत्री को स्पष्टवादिता के लिए प्रेरित करेगी। इस प्रकार अनेक देशों से संबंधों के मामले में प्रधानमंत्री और उनके राजनयिकों को 'स्वर्ण स्वतंत्रताओं' तथा प्रेस की स्वतंत्रता, आदि शामिल थे। भारत का जीवन्त लोकतंत्र के रूप में बेदाग रिकार्ड है जहाँ जनसंख्या अत्यधिक विविधतापूर्ण है। भारत ऐसे परिवेश में है जहाँ अनेक गैर-लोकतांत्रिक व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं। यह

तथ्य भी नहीं भुलाया जाना चाहिए कि हम चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। राज्य और राष्ट्र प्रमुख के रूप में लगभग तीन दशक का अनुभव रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए राजनय नई बात नहीं है। आम चुनाव के पहले अनेक साक्षात्कारों में उन्होंने भारत की 'वैश्विक छवि' बनाने के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं। जी 20 में भारत शानदार परीक्षा राजनयिक वार्ताओं के फलस्वरूप एक संयुक्त बयान जारी करने में सफल हुआ है। इसके साथ ही अनेक उच्चस्तरीय विदेश यात्राओं, नागरिकों व पड़ोसियों के लिए अनेक बचाव अभियानों, कोविड के दौरान आपातकालीन औषधियों की सप्लाई, आदि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा वैश्विक प्रबंधन में सम्मान का कारण बने हैं। प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में जी 7 नेताओं के साथ उनकी बैठकें निरंतरता का प्रतीक हैं। इसके साथ ही उन्होंने वर्तमान तथा संभावित नए सहयोगियों के साथ नए संबंधों के रोडमैप तैयार किए हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इटली यात्रा ऐसे समय हुई है जब यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है तथा अनेक बाधाओं के बावजूद आक्रमणकारी रूस के खिलाफ एक संयुक्त यूरोपीय दृष्टिकोण उभर कर सामने आ रहा है। इनमें से अनेक की इजराइल के 'आतंक के खिलाफ युद्ध' पर भी समान चिन्ताएँ हैं जो कई महीनों से जारी है। उल्लेखनीय है कि इजराइल और रूस भारत के निकट सहयोगी हैं, ऐसे में भारत को इन परिवर्तनशील स्थितियों के बारे में टिप्पणी करने में अत्यधिक सतर्कता बरतनी होती है। अब तक वह ऐसा करने में सफल रहा है। अतीत के संबंधों की गतिशीलता पर गहरें संबंध बनाने के साथ अमेरिका जैसे नए सहयोगियों के साथ संबेदनशील राजनय का परिचय देना होगा।

कोई आश्चर्य नहीं कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने परिपक्व राजनयिक व विदेश मंत्री एस. जयशंकर को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना है। अपने पिछले कार्यकाल में विकसित विदेश नीति निरंतरता बनाए रखने पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है। उभरती भू-राजनीतिक स्थितियों में भारत की भूमिका का लगातार परीक्षण आने वाले दिनों में भी होता रहेगा।

आप की बात

रक्तदान का महत्व

दुनिया भर के वैज्ञानिक ऐसे युनिवर्सल डोनर ब्लड की तलाश में हैं जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सके। वैसे तो ओ ब्लड ग्रुप वाले युनिवर्सल डोनर माने जाते हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। नेचर माइक्रो ब्यालॉजी में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने इस समस्या के समाधान में सहायक तरीका खोजा है। यह चिकित्सा के इतिहास में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हमारे देश में ब्लड डोनेशन को लेकर बहुत उदासीनता और पूर्वाग्रह व्याप्त हैं। इसे देखते हुए अब ब्लड देने वाले व्यक्ति के परिजनों को उतने यूनिट ब्लड का डोनेशन करना जरूरी कर दिया गया है। फिर भी मानव जीवन

निरर्थक कयासबाजी

लोकसभा चुनाव में कम सीटें मिलने पर भाजपा और आरएसएस के संबंधों में दूरियाँ बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कुछ मुद्दे उठाए थे जिनको भी भाजपा और आरएसएस के बीच दूरी का प्रमाण बताया गया। इस दुष्प्रचार के बाद आर्थिक विकास किसी भी देश की नींव होते हैं और इन मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति आयोग का गठन किया जाना चाहिए जिसमें सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार शामिल हों। यह आयोग नियमित अंतराल पर मिलकर राष्ट्रीय हितों से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से निर्णय लें। इससे न केवल त्वरित और प्रभावी नीति निर्माण संभव होगा, बल्कि देश की एकता और

राष्ट्रीय सहमति

अखंडता भी बनी रहेगी। मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सनसनीखेज समाचारों से बचते हुए राष्ट्रीय हितों पर ध्यान केंद्रित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। हमें बच्चों को शुरू से ही राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता की महत्ता समझानी चाहिए। यदि हम सभी मिलकर एकजुट होकर काम करें तो निस्संदेह हमारा देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सहमति का विकास जरूरी है।

परीक्षाओं पर सवाल

आजकल अनेक परीक्षाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी इस प्रदेश में पेपर लीक की घटना तो कभी उस प्रदेश में, कभी परीक्षार्थी सड़क पर उतर रहे हैं तो कभी वे कोर्ट की सीढ़ी नाप रहे हैं, कभी नेट की परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं तो कभी नेट के और कभी अन्य परीक्षाओं के। कभी परीक्षाएँ रद्द हो रही हैं तो कभी सीबीआई जांच के आदेश आ रहे हैं। आखिर अभ्यर्थियों और परीक्षार्थियों के साथ ऐसा मजाक क्यों चल रहा है? कितनी मेहनत, समय और धन खर्च करके हजारों-लाखों विद्यार्थी अनेक स्तर पर प्रतियोगी परीक्षाएँ देते हैं। उनमें जो पास हो जाते हैं वे उम्मीद लगा लेते हैं अपने अगले करियर की ओर पता लगता है कि पेपर लीक होने के कारण सब कुछ रद्द हो गया। ऐसे में क्या गुजरती होगी उन पर और उनके परेंट्स पर। सरकार सख्त कदम उठाये ताकि विद्यार्थियों का भविष्य बनते-बनते रकने न जाए और न ही परीक्षाएँ सरकार की क्षमता व निष्ठा पर सवाल उठाने का कारण बनें। भारत अनेक क्षेत्रों में दुनिया में अग्रणी है, फिर वह ठीक से परीक्षाएँ कराने में बार-बार विफल क्यों होता है?

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।

प्रत्येक परिवार के पास हो फैमिली आईडी, हर वंचित को मिलेगा योजनाओं का सीधा लाभ: योगी

● मुख्यमंत्री का निर्देश, जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश की प्रत्येक परिवार इकाई को जारी की जा रही 'परिवार आईडी' प्रक्रिया की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की और इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ सभी परिवारों को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक सदस्य को रोजगार-सेवायोजन से जोड़ने के संकल्प के क्रम में प्रदेश में परिवार आईडी जारी की जा रही है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में निवासरत लगभग 3.60 करोड़ परिवार के 15.07 करोड़



लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ पा रहे हैं। इन परिवारों की राशनकार्ड संख्या ही फैमिली आईडी है। जबकि 1 लाख से अधिक गैर राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी जारी की जा चुकी है। ऐसे परिवार जो कि राशन कार्ड धारक नहीं हैं, उनके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन कर परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था है। इस योजना का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार किया जाए।

प्रदेश का कोई भी परिवार इससे वंचित न रहे। एक परिवार-एक

पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी किया जा रहा है, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित होगा। यह डेटाबेस लाभाभ्यास योजनाओं के बेहतर प्रबंधन, समयबद्ध लक्ष्यकरण, पारदर्शी संचालन एवं योजना का शत-प्रतिशत लाभ प्राप्त व्यक्तियों तक पहुंचाने और आम जनता को सरकारी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने की व्यवस्था के सरलीकरण में सहायक होगा। परिवार आईडी प्रदेश के सभी परिवारों के लिए है। 25

करोड़ जनता को इसका लाभ मिलना चाहिए। परिवार आईडी के माध्यम से प्राप्त एकीकृत डेटाबेस के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों का चिन्हंकन कर उन्हें रोजगार के समुचित अवसर प्रार्थमिकता पर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। केंद्र व राज्य सरकार संचालित 76 योजनाओं/सेवाओं को फैमिली आईडी से लिंक किया जा चुका है। अवशेष सभी लाभाभ्यास योजनाओं को परिवार आईडी से लिंक किया जाए। केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित समस्त योजनाओं का

डेटाबेस प्राप्त कर उसे परिवार कल्याण पास बुक एवं फैमिली आईडी से जोड़ा जाना चाहिए। सभी लाभाभ्यास (डीबीटी) योजनाओं/सेवाओं के ऑनलाइन आवेदन में आधार आवेदन एवं आधार अधिप्रमाणन अनिवार्य किया जाना चाहिए। इस तरह फैमिली आईडी का कवरेज बढ़ाने में सहायता मिलेगी। आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों में नए प्रवेश के समय आधार ऑर्थेंटिकेशन कराए, तदोपरान्त परिवार आईडी से लिंक किया जाए। जाति और आय प्रमाण पत्र जारी करने में अनावश्यक देरी न हो। इस प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए। सीएम ने कहा कि हर एक परिवार को मिल रहे शासकीय योजनाओं के लाभ का पूरा विवरण दर्शाते हुए परिवार का पासबुक भी तैयार कराया जाए। पास-बुक और परिवार आईडी जारी करने से पूर्व परिवार के संबंध में सभी जानकारी को विधिवत प्रमाणित किया जाए।

किसी भी सूत्र में कब्जा बर्दाश्त नहीं, ऐसा करने वालों पर हो कठोर कार्रवाई: योगी

● मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में सुनी आमजनत की पीड़ा, समस्याओं का समय से निस्तारण करने दिए निर्देश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' किया। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न कोंनों से पहुंचे सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा सुनाई। सीएम ने प्रत्येक पीड़ितों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समयसमया के अंदर समाधान के निर्देश दिए। जनता दर्शन कार्यक्रम में महिलाएं, पुरुष व युवाओं ने अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में पहुंचे प्रत्येक पीड़ितों से मुलाकात की। सीएम ने उनकी समस्याओं को सुना, फिर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीड़ितों को समय सीमा के अंदर न्याय मिले। किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन में पुलिस की



प्रताड़ना से सम्बंधित शिकायत को मुख्यमंत्री ने गम्भीरता से लिया। बोले कि पीड़ितों के प्रति पुलिस संवेदनशील रहे और स्थानीय स्तर पर ही सुनवाई सुनिश्चित होती रहे। वहीं उपचार के लिए आर्थिक सहायता के प्रार्थना पत्र भी आए, जिस पर मुख्यमंत्री ने कागजी कार्रवाई कर मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जमीन पर कब्जे की शिकायत को लेकर आए पीड़ितों को भी सीएम ने आश्वासन

किया कि कहीं भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि जमीन कब्जा की शिकायत पर सख्ती बरतते हुए इस पर अंकुश लगाया जाए। वहीं युवाओं ने भी अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को रूबरू कराया, जिस पर उन्हें भी त्वरित समाधान का आश्वासन मिला। सीएम ने सभी प्रार्थना पत्रों का समय सीमा के अंदर निस्तारण कर पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने का भी निर्देश दिया।

उपचुनाव में उतरेगी बसपा प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बैठक बाद

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हलचल तेज हो गयी है। ऐसा माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में एक भी सीट न लाने वाली बसपा उपचुनाव से जमीनी स्तर पर अपनी ताकत का आंकलन करेगी। हालांकि अमूमन बसपा उपचुनाव से दूर ही रही है। पिछले दो बार बसपा मैदान में उतर रही है। उपचुनाव में मायावती के उम्मीदवार चुनवी मैदान में आने से सपा-बीजेपी की राह आसान नहीं रहेगी। माना जा रहा है कि बसपा अध्यक्ष मायावती 23 जून को लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगी। इस बैठक में ही यूपी उपचुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो रणनीति बनाएंगी और प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगाने की संभावना है। बता दें कि चुनाव आयोग ने सात राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। वहीं यूपी की 10 सीटों पर भी चुनाव होना है। इनमें फूलपुर, मखवा, मीरजापुर, मिल्कीपुर, करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटेहरी और खैर विधानसभा सीटें हैं।

सौर ऊर्जा से रोशन होगा अयोध्या गोरखपुर व वाराणसी शहर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत निदेशक भूषण की अध्यक्षता में सौर सेल सेल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में नगर निगमों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने हेतु गैठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक गुरुवार को बापू भवन सचिवालय स्थित उनके कार्यालय कक्ष में हुई। उल्लेखनीय है कि सोलर सिटी कार्यक्रम के अन्तर्गत अयोध्या, गोरखपुर एवं वाराणसी शहरों की कुल विद्युत खपत का 10 प्रतिशत सौर ऊर्जा से प्राप्त किया जाना है। बैठक में नगर निगम अयोध्या में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, नगर निगम गोरखपुर में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट एवं सोलर स्ट्रीट लाइट तथा नगर निगम वाराणसी में स्मार्ट सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर हाई मास्ट, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर ट्री एवं वॉटर किऑफ़ की स्वीकृति प्रदान करने के साथ अन्य प्रस्तावों पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गयी। उल्लेखनीय है कि अयोध्या सोलर सिटी के अन्तर्गत सरयू नदी के तट पर स्थापित हो रहे 40 मेगावाट सोलर पावर प्लांट में से 14 मेगावाट की स्थापना हो चुकी है, शेष 26 मेगावाट का कार्य प्रगति पर है। साथ ही अयोध्या, गोरखपुर व वाराणसी में 'पीएच सूर्य घर पुस्त बिजली योजना' के अन्तर्गत घरलू क्षेत्र के उपभोक्ताओं को आच्छादित करने हेतु क्रमशः 50000, 75000 तथा 75000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसको प्राप्त करने हेतु नगर निगम एवं मुख्य विकास अधिकारी को कार्ययोजना तैयार करने तथा इसके बृद्ध प्रचार-प्रसार करने के निर्देश प्रदान किए गए।

माता विंध्यवासिनी देवी से जुड़ीं कथाओं को किया जाएगा शोकेस, आर्ट गैलरी बनेगी माध्यम मीरजापुर में 3.43 करोड़ रुपए की लागत से कराया जाएगा निर्माण, कार्ययोजना को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया शुरू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/मीरजापुर

उत्तर प्रदेश की आध्यात्मिक चेतना के केंद्रों को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध योगी सरकार ने श्री काशी विश्वनाथ धाम और अयोध्या के कायाकल्प के बाद मीरजापुर में माता विंध्यवासिनी देवी के धाम को भी नव्य-भव्य रूप देने की शुरुआत कर दी है। यहां आने वाले भक्तों को अब माता विंध्यवासिनी की लीलाओं से जुड़ी कथाओं और तीर्थ के माहत्व को दर्शाने वाली विभिन्न कलाकृतियों को आर्ट गैलरी के माध्यम से शोकेस किया जाएगा। आर्ट गैलरी के निर्माण ये यहां आने

वाले पर्यटकों को आस्था, कला और संस्कृति का अनुभूत संगम देखने को मिलेगा। उल्लेखनीय है कि भगवती विंध्यवासिनी आद्या महाशक्ति हैं तथा विन्ध्याचल सदा से उनका निवास-स्थान रहा है। यही कारण है कि विंध्यगिरि को एक जागृत शक्तिपीठ माना जाता है और न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश-दुनिया से भक्त माता विंध्यवासिनी के चरणों में निरंतर शीश नवाने आते हैं। विंध्य कॉरिडोर योजना के अंतर्गत मां विंध्यवासिनी माता मंदिर के अंतर्गत परिक्रमा पथ समेत विभिन्न प्रकार के निर्माण व विकास कार्यों को गति दी जा रही है। इसी

क्रम में, आर्ट गैलरी के निर्माण के जरिए विंध्य क्षेत्र के पर्यटन विकास की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। गौरतलब है कि सीएम योगी की मंशा अनुरूप मीरजापुर व विंध्य क्षेत्र के समेकित विकास का जो खाका खींचा गया था उसे क्रियान्वित करते हुए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। यही कारण है कि आर्ट गैलरी के निर्माण कार्य को गति देने की प्रक्रिया भी तेज हुई है। आर्ट गैलरी के निर्माण का जिम्मा यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) को सौंपा गया है। यूपीपीसीएल द्वारा कार्यों की पूर्ति के लिए स्पेशलाइज्ड

एजेंसियों को नियुक्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ई-निविदा माध्यम के जरिए संबंधित एजेंसियों को नियुक्त के लिए यूपीपीसीएल ने आवेदन मांगे हैं। गौरतलब है कि आर्ट गैलरी से संबंधित सभी निर्माण कार्यों को 3.43 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। कार्यावृत्त के बाद नियुक्त एजेंसियों को वर्षा अवधि के अतिरिक्त 6 माह में सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। विंध्य कॉरिडोर योजना के अंतर्गत मां विंध्यवासिनी माता मंदिर के अंतर्गत परिक्रमा पथ परकोटा (ए ब्लॉक) से लेकर एच ब्लॉक

(क ब्लॉक) बनाया जा रहा है। परकोटों के छत पर ए ब्लॉक से लेकर एच ब्लॉक तक कुल आठ केंद्र बिंदु हैं। 16 स्थानों पर मंदिर का अलग-अलग गुम्बद नुमा डिजाइन पथरों से बनाया जा रहा है। यहां देवी-देवताओं की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी जो मां विंध्यवासिनी मंदिर की छत से इसकी भव्यता एवं दिव्यता प्रदर्शित करेगी। इसके अतिरिक्त, गलियों का चौड़ीकरण करने के पश्चात सड़क के बीच डिवाइडर का भी निर्माण कार्य चल रहा है। डिवाइडर को तरह-तरह के रंग बिरंगी पौधे, आर्क लैंप और रोशनी सज्जा युक्त किया जाएगा।

भाजपा सरकार में पेपर माफिया छात्रों के भविष्य से लगातार कर रहे हैं खिलवाड़: अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि फरवरी माह में पुलिस भर्ती व समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद अब नीट परीक्षा को मजक बना दिया गया है। अब यूपीसी-नेट 2024 की परीक्षा भी लीक होने के बाद रह गई गयी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में पेपर माफिया एक के बाद एक परीक्षा के पेपर लीक कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पेपर लीक किसी को भी देश के खिलाफ बड़ी साजिश हो सकती है? यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर लीक होगा तो कानून-व्यवस्था नहीं सुधरेगी। जिससे देश-प्रदेश में अशांति और अस्थिरता बनी रहेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हथशस्त्र की परीक्षा में घपला होगा तो ईमानदार लोग डॉक्टर नहीं बन पाएंगे और देश के लोगों के इलाज के लिए भविष्य में डॉक्टरों की कमी और बढ़ जाएगी और बेईमान लोग, जनता के जीवन के लिए खतरा बन जाएंगे। यादव ने कहा कि नीट की परीक्षा न होने से, पहले से शिक्षकों की जो कमी चली आ रही है, उसमें और भी ज्यादा इजाफा होगा। शिक्षकों की कमी से देश के मानसिक



विकास में बाधा उत्पन्न होगी, जो कालांतर में देश के लिए बेहद घातक साबित होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि इन सबसे प्रशासन के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था चौपट हो जाएगी। ये हमारे देश के शासन-प्रशासन व देश के मानव संसाधन के विरुद्ध कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम निकलेंगे। इसीलिए कोर्ट की निगरानी में इसकी कठोर जांच हो और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाए, और कोई भी अपराधी छोड़ा न जाए, फिर वो चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो या फिर उसके सिर पर सत्ता का हाथ ही क्यों न हो? यादव ने कहा कि लोग कह रहे हैं कि भ्रष्ट लोग कोरोना के वैक्सिन में चुनवी चंदे के नाम पर पीछे से करोड़ों रुपए खा सकते हैं, वो भला परीक्षा-प्रणाली को क्या छोड़ेंगे? अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार कोई परीक्षा पारदर्शिता से नहीं करा पा रही है। भर्ती परीक्षाओं के कई पेपर पहले ही लीक हो चुके हैं। भाजपा सरकार ने छात्रों, नीजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है।

नीट-यूजी परीक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस आज विधानमवन का घेराव कर करेगी प्रदर्शन



पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि नीट-यूजी-2024 का परिणाम 4 जून 2024 को जारी हुआ था। जिसमें कई अनियमितताएं जाहिर हुईं, पेपर लीक का आरोप भी अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया। परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां, कदाचार और अनुचित साधनों का प्रयोग किया गया। भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, और हरियाणा में नीट परीक्षा से सम्बंधित भ्रष्टाचार के लिए कई लोगों की गिरफ्तारियां भी हुईं जिससे पूरी परीक्षा ही दोषपूर्ण की आशंका से ग्रसित हो गई है। देश एवं भाजपा शासित प्रदेशों में जिस तरह युवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन पचां लीक की घटनाएं हो रही हैं, कांग्रेस पार्टी इसकी भर्त्सना करती है और कल पूरे देश

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बैठक कर तय की प्रदर्शन की रणनीति

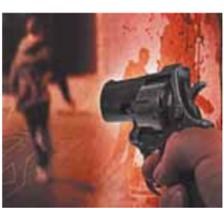
में इस अराजकता के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। इसी क्रम में कल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव किया जायेगा। देश के भविष्य युवाओं के अधिकारों के लिए लड़ी जा रही इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने के लिए आज एक तैयारी बैठक भी की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि नीट परीक्षा में भ्रष्टाचार के कारण लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। अभिभावकों के लाखों रुपए बर्बाद हुए हैं, जिस कारण कई छात्र अवसाद में हैं और कईयों ने तो आत्महत्या कर ली है।

चुनाव खत्म होते ही पुलिस का अभियान हुआ तेज

15 दिन में 9 बड़े अपराधियों पर कसा शिकंजा, एनकाउंटर में दो ढेर, 96 घायल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

यूपी में निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के साथ ही विभिन्न पर्व-त्योहारों की सकृशल संपन्न कराने वाली यूपी पुलिस का इकबाल एक बार फिर चुलंदी पर है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति को अमलीजामा पहनाने में जुटी यूपी पुलिस की निगाहें अपराधियों के खिलाफ दोबारा टेढ़ी हो चुकी हैं। बीते 15 दिनों की रिपोर्ट पर नजर डालें तो बदमाशों के खिलाफ चली 79 ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों के पांव एक बार फिर उखड़ने शुरू हो गये हैं। 4 जून से 19 जून के बीच हुए इन मुठभेड़ों में दो



दुर्दांत बदमाशों को ढेर किया जा चुका है, जबकि 96 अपराधी घायल हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान अबतक 139 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। हालांकि इन मुठभेड़ों के दौरान सात पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के अनुसार राज्य स्तर के

चिह्नित 68 माफिया गैंग के सदस्य और सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। अबतक विभिन्न माफिया गिरोह के 9 सदस्यों के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की गई है। इनमें से तीन को गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 1 के खिलाफ गैंगेस्टर और 2 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इसके अलावा भदोही के माफिया विजय मिश्रा के खिलाफ विचाराधीन अभियोग में न्यायालय में सघन पैरवी करते हुए बीते 13 जून को उसे सजा दिलाई जा चुकी है। हालांकि इन मुठभेड़ों के दौरान सात पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के अनुसार राज्य स्तर के

बताया कि कानपुर के सऊद अख्तर गैंग का शाहिन अपराधी आसिफ उर्फ पप्पू स्मार्ट पर भी 25 हजार का इनाम घोषित था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यही नहीं अंबेडकरनगर के अजय सिंह उर्फ सिपाही गैंग के सक्रिय सदस्य उत्कर्ष सिंह को भी एस्टीएफ ने दबोच लिया है। उत्कर्ष पर भी 25 हजार का इनाम घोषित था। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के कुख्यात माफिया सुशील उर्फ मूंडू को 4.4570 हेक्टेयर जमीन को कुर्क किया गया है, जिसकी कीमत साढ़े चार करोड़ रुपए आंकी गई है। वहीं मुठभेड़ों के दौरान सात पुलिसकर्मी प्रशांत सिंह उर्फ प्रिंस और मुजफ्फरनगर के दुर्दांत निलेश राय को ढेर किया जा चुका है। उन्होंने

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

2.35 लाख से ज्यादा युवा हुए प्रशिक्षित, 1.25 लाख को मिला रोजगार

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत योगी सरकार ग्रामीण युवाओं की क्षमता को पहचानकर उन्हें उनकी रुचि के आधार पर रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। इस योजना के तहत अब तक 2,35,334 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है और 1,25,822 युवाओं को सेवायोजित किया गया है। यह योजना विशेष रूप से बीपीएल सूची में शामिल परिवारों के 15-35 आयुवर्ग के सदस्यों (महिलाओं के लिए 15-45 वर्ष), मनरेगा के श्रमिकों, बेरोजगारों, अल्प शिक्षित अथवा स्कूल ड्रॉपआउट को लक्ष्य बनाती है। उल्लेखनीय है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वें जन्मदिवस के अवसर पर भारत

सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में यह योजना उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जा रही है। प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ग्रामीण युवाओं की क्षमता को पहचानकर उन्हें उनकी रुचि के आधार पर रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। युवाओं को आधुनिक कक्षाओं और लैब में प्रशिक्षण के साथ-साथ निःशुल्क आवास, भोजन, प्रशिक्षण सामग्री, यूनिफॉर्म आदि की सुविधा भी प्रदान

की जा रही है। विभिन्न विषयों जैसे अपैरल, ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेल्नेस, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, डॉमेस्टिक वर्क्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, फूड प्रॉसेसिंग, ग्रीन जॉब्स, लेदर, आईटी-आईटीईएस, लॉजिस्टिक्स, पावर, रिटेल, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, मोलिकम, टेक्सटाइल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी आदि के साथ-साथ सांफ्ट स्किल्स भी सिखाई जा रही है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने हुनर से स्वावलंबी बनाकर विकास के कीर्तिमान स्थापित करने में सक्षम बनाना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवाओं को कौशल से जोड़कर उनके भविष्य को उज्वल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है।

मैं राजभवन में तैनात मौजूदा पुलिस दल के साथ सुरक्षित नहीं : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बोस

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें राजभवन में तैनात कोलकाता पुलिस के मौजूदा दल की वजह से अपनी सुरक्षा को खतरा होने का अंदेशा है। बोस ने हाल ही में पुलिस कर्मियों को राजभवन परिसर खाली करने का आदेश दिया था, जिसके कुछ दिनों बाद यह बयान आया है। हालाँकि, पुलिसकर्मी अभी भी राज्यपाल भवन में तैनात हैं। बोस ने कहा, मेरे पास कारण हैं, जिनकी वजह से मुझे लगता है कि मौजूदा प्रभारी और उनका दल मेरी निजी सुरक्षा के लिए खतरा है।

उन्होंने कहा, मैंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सूचित किया कि राजभवन में कोलकाता पुलिस के साथ मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूँ लेकिन कोई कार्वाई नहीं हुई। राजभवन के सूत्रों ने बताया कि

बोस ने राज्य सरकार से राजभवन में तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार जासूसी किए जाने की शिकायत की और उन्हें लगता है कि वे बाहर के प्रभावशाली लोगों के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। बोस ने कहा, यहाँ तैनात पुलिसकर्मी मेरी और मेरे अधिकारियों की गतिविधियों की जासूसी कर रहे हैं। उन्हें (पुलिसकर्मियों) सरकार में बैठे अपने राजनीतिक आकाओं का मौन समर्थन प्राप्त है। यह संविधान में स्पष्ट है। राज्यपाल ने यह मामला समय-समय पर बनर्जी के संज्ञान में लाया है लेकिन अब तक इसपर कोई कार्वाई नहीं हुई।

मुख्यमंत्री गुर्गु विभाग का कार्यभार भी संभालती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, पुलिस विभाग में आला अधिकारियों की जानकारी के बिना ऐसा कुछ भी संभव नहीं है और पुलिस गुर्गु विभाग के अंतर्गत आती है।

बोस ने दावा किया कि राजभवन में वर्तमान प्रभारी अधिकारी के अधीन तैनात पुलिस दल के गलत कार्यों के बारे में उन्हें जानकारी थी। विभिन्न स्रोतों से यह विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ तैनात पुलिस दल राजभवन तथा लोगों के हितों के खिलाफ काम कर रहा है। मैंने खुद भी इसकी पुष्टि की है। बोस ने कहा कि यहाँ तैनात कुछ पुलिसकर्मी पहले राज्य सचिवालय नबन्ना में तैनात थे। राज्यपाल ने कहा, वे किसी के लिए जासूस के रूप में काम कर रहे हैं। मैं अभी उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता।

बोस ने नवंबर 2023 में भी राजभवन में जासूसी का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया था। उन्होंने भूतल को छोड़कर राजभवन के अंदर कोलकाता पुलिस कर्मियों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था। उनके पूर्ववर्ती जगदीप धनखड़ ने भी

राजभवन के अंदर कोलकाता पुलिस कर्मियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया हुआ था। धनखड़ वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति हैं। बोस ने कहा, मेरे पूर्ववर्ती राज्यपाल और मैंने कोलकाता पुलिस को राजभवन के केवल कुछ क्षेत्रों में ही तैनाती की अनुमति दी थी, जो गेट के निकट हैं और सिर्फ भूतल तक ही सीमित है। लेकिन मैंने पाया कि लिफ्ट के पास मेरे आगंतुकों पर नजर रखने के लिए पुलिसकर्मी अनधिकृत रूप से मौजूद हैं। उन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया और वहां से चले जाने को कहा गया। वे राजभवन में प्रभारी अधिकारी और बाहर के लोगों को सूचनाएं देते हुए पाए गए। इसे आपराधिक कृत्य कहा जा सकता है। राज्यपाल ने कहा, अगर राजभवन में तैनात पुलिस बल द्वारा आपराधिक गतिविधियों की जा रही है तो उसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार होना चाहिए।

केंद्र महज मूकदर्शक बना नहीं रह सकता, वह आगे बढ़कर आरक्षण मुद्दे को हल करे: पवार

भाषा। पुणे

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (रकांपा) के प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र महज मूकदर्शक बना नहीं रह सकता और उस संघटा समुदाय तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आरक्षण की मांग से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए आगे आना चाहिए। महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा-ओबीसी संबंध बढ़ने के बारे में पूछे जाने पर पवार ने कहा कि इसका एक ही समाधान है कि केंद्र आगे बढ़कर इसे सुलझाने के लिए पहल करे। पवार ने कहा कि कानून और राज्य तथा केंद्र की नीतियों में संशोधन की जरूरत है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र के पुणे जिले के बारामती में पत्रकारों से बातचीत में यह बात कही।

महाराष्ट्र विधानसभा ने इस साल फरवरी में सर्वसम्मति से एक विधेयक पारित किया जिसमें मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में एक अलग श्रेणी के तहत 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। हालाँकि संसुदाय ओबीसी के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे उस मसौदा

विधिसूचना के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं जो कुनबियों को मराठा समुदाय के लोगों के सगे सौयारे (रक्त संबंधी) के रूप में मान्यता देता है। जरांगे साथ ही कुनबियों को मराठा के रूप में पहचान देने संबंधी एक कानून बनाने की भी मांग कर रहे हैं।

कुनबी, एक कृषि समूह है, जिसे ओबीसी श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ मिलता है। मराठा आरक्षण की मांग के बीच दो ओबीसी कार्यकर्ता पिछले सप्ताह से जालना जिले में अनशन पर बैठे हैं और सरकार से यह आश्वासन मांग रहे हैं कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूदा आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाए। इस पर पवार ने कहा, राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कहा, सरकारों खासतौर पर केंद्र को दोनों समुदायों की मांगों को पूरा करने के लिए आगे आना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन कोई सीमा पार न करे और सामाजिक तनाव पैदा न हो। सरकारें इस मुद्दे पर महज मूकदर्शक बनी नहीं रह सकतीं। उन्होंने कहा कि अगर सकारा सकारात्मक कदम उठाए तो विपक्ष इस पर राजनीति नहीं करेगा।

चीनी मिल पर हंगामा करने के मामले मे पूर्व विधायक सहित छह को सात-सात साल की कैद रामपुर (उप्र)। रामपुर की विशेष एमपीएमएलए अदालत ने शाहबाद की एक चीनी मिल में घुसकर मारपीट के आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कशीराम दिवाकर समेत छह लोगों को सात-सात साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी छह आरोपियों को बंधुवार को दोषी करार दिया था और आज उन्हें सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने बताया कि शाहबाद स्थित राणा चीनी मिल के अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने 16 जनवरी 2012 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि चीनी मिल में ट्रैक्टरदूली निकलने को लेकर हुए विवाद में भूतपूर्व विधायक कशीराम दिवाकर की अगुवाई में लोगों की भीड़ ने मिल में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ की थी जिसमें कुछ कर्मी भी घायल हुए थे। न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में पूर्व विधायक कशीराम दिवाकर, कृष्णपाल, भात, संजू यादव, मेहराज और सुरेश गुप्ता नामक अभियुक्तों को को दोषी करार दिया था।

पेज 1 का शेष नीट के बाद...

बस इस विषय पर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। राजस्थान में पेपर लीक हुआ लेकिन राहुल गांधी ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला। यूजीसी-नेट भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति और पीएचडी में प्रवेश के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, पुरस्कार के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा है। एनईईटी-यूजी परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि एनईईटी 'पेपर लीक' में गिरफ्तार मुख्य आरोपी का संबंध राजद नेता तेजस्वी यादव से जुड़े अधिकारियों से है, और उन्होंने इसकी जांच की मांग की। उपमुख्यमंत्री ने कहा, यादव से जुड़ा अधिकारी सिक्ंदर के लिए पटना और अन्य संस्थानों के गेस्ट हाउस में आवास की व्यवस्था करता था। मेरे पास उन संदेशों का विवरण है जो अधिकारी ने सिक्ंदर के लिए

कर्नाटक में रह रहे लोगों को कन्नड़ सीखना चाहिए: सिद्धरमैया

भाषा। बैंगलुरु

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बृहस्पतिवार को लोगों से अपनी मातृभाषा बोलने में गर्व महसूस करने का अनुरोध करते हुए कहा कि कन्नड़ भाषा, भूमि और जल की बचाना हर कन्नडिगा का दायित्व है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में रह रहे लोगों को कन्नड़ सीखना चाहिए। उन्होंने राज्य में कन्नड़ माहौल बनाने की जरूरत पर बल दिया। यहां विधान सौध के परिसर में नदा देवी भुवनेश्वरी की 25 फुट ऊंठी कांथ्य प्रतिमा के निर्माण के वास्ते भूमि पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी मातृभाषा बोलना गर्व का विषय होना चाहिए। उन्होंने कहा, एक संकल्प लिया जाए कि राज्य में कन्नड़ के सिवा कोई भाषा नहीं बोली जाए। कन्नडिगा उदार होते हैं। यही कारण है कि कन्नड़ में ऐसा माहौल है कि जो दूसरी भाषाएं बोलते हैं, वे भी कन्नड़ सीखे बिना रह सकते हैं।

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में ऐसी स्थिति नजर नहीं आ सकती है। वे बस अपनी मातृभाषा में ही बोलते हैं। कन्नडिगाओं से अपनी मातृभाषा में बोलने का अनुरोध करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि इसे लेकर हीनाता का बोध नहीं पालने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें भी अपनी मातृभाषा में बोलना है। उनसे हमें गर्व महसूस करना चाहिए। कर्नाटक में रह रहे लोगों से कन्नड़ सीखने का आवाहन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, कन्नड़ माहौल तैयार करना हम सभी का दायित्व है। उसके लिए यहां रहने वाले सभी लोगों को कन्नड़ सीखना चाहिए। हम उस तरह चुप नहीं रह सकते। कन्नड़ ढीठ नहीं होते हैं। लेकिन कन्नड़ के प्रति प्यार विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, अन्य राज्यों की भांति हमें हठधर्मी नहीं बनना चाहिए। लेकिन हमें अपने अंदर अपनी भाषा, भूमि और अपने देश के प्रति सम्मान एवं प्रशंसा (का भाव) विकसित करना चाहिए।

कंचनजंघा हदसा में मालगाड़ी के चालक दल एवं मंडल के परिचालन विभाग की चूक सामने आई : जांच दल

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 17 जून के कंचनजंघा एक्सप्रेस हदसे की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि न्यू जलपाईगुड़ी रेल मंडल के परिचालन विभाग और यात्री ट्रेन से टकराने वाली मालगाड़ी के चालक दल की चूक की दार्जिलिंग जिले में सोमवार को सिषाव्यवह जाने वाली कंचनजंघा एक्सप्रेस से टकराने के बाद यात्री ट्रेन के गार्ड और मालगाड़ी के चालक (लोको पायलट) सहित कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के तुरंत बाद रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा ने कहा था कि गति संबंधी नियम का पालन नहीं किया गया और ट्रेन की गति के कारण यह घटना हुई होगी। एनजेपी मंडल के मुख्य लोको इंस्पेक्टर (सीएलआई) ने अपने असहमित नोट में कहा कि 17 जून, 2024 को सुबह 5:50 बजे नजे स्वचालित और अर्ध-स्वचालित सिग्नल काम नहीं कर रहे थे।

उन्होंने रेल नियमों का हवाला देते

सीजेआई और साथी न्यायाधीश 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेंगे

नई दिल्ली। भारत के प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और उच्चतम न्यायालय के उनके साथी न्यायाधीश शुक्रवार को आयोजित होने वाले 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) समारोह में भाग लेंगे। शीर्ष अदालत के ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है, इक्कीस जून 2024 को 10वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, उच्चतम न्यायालय के विस्तारित भवन परिसर के सी ब्लॉक में द्वितीया तल पर स्थित सभागार और ए ब्लॉक के चतुर्थ तल पर स्थित योग एवं मनोरंजन हॉल में रजिस्ट्री के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश और साथी न्यायाधीश इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपनी भागीदारी से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। योगासन योग विशेषज्ञों की देखरेख में करए जाएंगे। प्रतिभागियों को योग के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली टी-शर्ट वितरित की जाएंगी।

भारत की सभ्यता और संस्कृति में संवेदनशीलता और समावेशिता की जड़े काफी गहरी हैं : मुर्मू

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बृहस्पतिवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में संवेदनशीलता और समावेशिता की जड़ें मूल्यों के रूप में काफी गहरी समाई हुई हैं और इससे समाज की प्रगति को आंका जा सकता है। मुर्मू ने यहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान का दौरा किया। उन्होंने दिव्यांग बच्चों और छात्रों से बातचीत की। उन्होंने नवनिर्मित प्रोस्थिसिस एवं ऑर्थोसिस सेंटर का भी दौरा किया और रोगियों से बातचीत की और वहां शारीरिक रूप से दिव्यांग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उपलब्ध उन्नत सुविधाओं का अवलोकन किया। राष्ट्रपति ने सभा को संबोधित करते हुए समाज की प्रगति को आंकने में संवेदनशीलता और समावेशिता के



महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ए मूल्य भारत की संस्कृति और सभ्यता में गहराई से निहित हैं। उन्होंने कहा, जब हमारे प्रयास दिव्यांगजनों की जरूरतों के प्रति समावेशी और संवेदनशील होते हैं, तो कोई भी शारीरिक स्थिति सामान्य जीवन जीने में बाधा नहीं बन सकती है।

उन्होंने एथलीट दीपा मलिक, अरुणामा सिन्हा और अपनी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के.एस. राजन्ना जैसे व्यक्तियों की

ओडिशा में भाजपा की वरिष्ठ नेता सुरमा पाढ़ी निर्विरोध चुनी गईं विधानसभा अध्यक्ष

भुवनेश्वर। भाजपा की वरिष्ठ नेता सुरमा पाढ़ी बृहस्पतिवार को ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष निर्विरोध चुनी गईं। नयागढ़ जिले के रानपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार की विधायक पाढ़ी इस पद के लिए अकेली उम्मीदवार थीं। किसी अन्य उम्मीदवार के नहीं होने के कारण पाढ़ी को निर्विरोध चुन लिया गया। प्रोटेम स्पीकर आरपी स्वैन ने विधानसभा के विशेष सत्र में पाढ़ी के निर्वाचन की घोषणा की और उन्हें कार्यभार सौंपा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माढ़ी, उपमुख्यमंत्री केवी सिंह देव व प्रवाती परिता, नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक और सदन के अन्य सदस्यों ने विधानसभा की नई अध्यक्ष को बधाई दी। बीजू जनता दल (बीजद) की प्रमिला मलिक के बाद पाढ़ी, ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला हैं। पाढ़ी ने विधानसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा, मुझे इस गरिमामय सदन का अध्यक्ष चुनने के लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगी। मुख्यमंत्री ने नई अध्यक्ष को बधाई दी और सदन के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष सहित सभी सदस्यों से पाढ़ी के साथ सहयोग करने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष नवीन पटनायक ने कहा, मैं आपको (पाढ़ी को) 17वीं विधानसभा अध्यक्ष के रूप में बधाई देता हूँ। मुझे विश्वास है कि अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आप इस गरिमामय सदन की गरिमा को बनाए रखेंगी। मुझे यह भी उम्मीद है कि सदस्य सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता ताराप्रसाद बहिनीपति और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कपा) के एकमात्र विधायक लक्ष्मण मुंडा ने भी पाढ़ी को ओडिशा विधानसभा की अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी। पाढ़ी (63) इस बार रानपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने बीजद के सत्यनारायण प्रधान को 15,544 मतों के अंतर से हराया। पाढ़ी 2004 विधानसभा चुनाव में रानपुर से निर्वाचित हुई थीं और नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजद-भाजपा गठबंधन सरकार में सहकारिता मंत्री रही थीं। सितंबर 2023 में बीजद की वरिष्ठ नेता प्रमिला मलिक ने ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा था। ओडिशा की 147 सदस्य विधानसभा में सतारूढ भाजपा के 78 विधायक हैं।

जदयू सांसद के खिलाफ अदालत में परिवार पत्र दायर

मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की एक अदालत में पड़ोसी जिला सीतामढी से नवनिर्वाचित जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के विवादित बयान को लेकर उनके खिलाफ बृहस्पतिवार को शिकायत दर्ज की गई है। मुजफ्फरपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप कुमार कुशवाहा ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को अदालत में ठाकुर के खिलाफ उक्त परिवार पत्र दायर कराया। ठाकुर ने हाल ही में उन समुदायों का काम नहीं करने की बात कही थी जिन्होंने कथित तौर पर लोकसभा चुनाव में उनके प्रतिद्वंद्वियों को वोट दिया था। कुशवाहा के अधिकारिता हरिओम कुमार ने संवाददाताओं से कहा, अदालत ने हमारे मामले पर सुनवाई की तारीख दो जुलाई तय की है। हमने प्रार्थना की है कि आरोपी सांसद पर कुशवाहा समुदाय, मुसलमानों और यादवों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए भर्दवि की धारा 501 और 505 के तहत मामला दर्ज किया जाए। कई बार विधान पार्षद रह चुके ठाकुर इस बार सीएमएल से सांसद निर्वाचित घोषित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सांसद ने अफसोस जताया था कि कुशवाहा समुदाय ने राजग मतदाता होने के बावजूद उनके राजद प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ इसलिए वोट दिया क्योंकि विपक्षी दल ने समुदाय के कई लोगों को मैदान में उतारा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले ठाकुर ने यह भी शिकायत की थी कि मुसलमान उन्हें सिर्फ इसलिए वोट नहीं देते क्योंकि मेरी पार्टी भाजपा की सहयोगी है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के प्रति उनकी निष्ठा के लिए एनपीए के लिए हीटवेब के प्रति उनका प्रतिरोध है कि कंचनजंघा एक्सप्रेस एक खराब सिग्नल पर रूकी हुई थी, तभी मालगाड़ी ने पीछे से उसे टक्कर मार दी।

है और संबंधित सरकारी विभागों (एनडीएमए, एनपीसीसीएफएच, एनसीडीसी, राज्य) द्वारा विभिन्न सलाह जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग आदि) को दिव्ली में बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार, चल रही भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए हीटवेब के एक्शन प्लान के एक हिस्से के रूप में बचाव अभियान चलाया जाएगा और फुटपाथों, खुले समुदाय के लिए बचाव प्रदान करके बचाया जाएगा। ज राही है। उन्होंने कहा, चिलचिलाती धूप के लगातार संर्क में रहने से उन्हें हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जो जीवन के लिए खतरनाक स्थिति है। लक्षणों में चक्कर आना, भ्रम, शरीर का उच्च तापमान और दौरा शामिल है। स्वच्छ भेयजल तक पहुंच सीमित हो सकती है, जिससे निर्जलीकरण हो सकता है जिससे हीटस्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है और थकान, सिरदर्द और चक्कर आ सकते हैं। लगातार धूप में रहने के कारण सनबन, चकते और गर्म में फोड़े होना आम बात है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए दिव्ली सरकार ने अधिकारियों को बेचरों को फुटपाथों, पार्कों से निकालकर आश्रय गृहों में भेजने का निर्देश दिया है। दिव्ली के मंत्री सीरधु भारद्वाज ने बुधवार को दिव्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीएसएसआईबी) की जारी एक आदेश में कहा, दिव्ली में गर्मी का मौसम अपने चरम पर

है और संबंधित सरकारी विभागों (एनडीएमए, एनपीसीसीएफएच, एनसीडीसी, राज्य) द्वारा विभिन्न सलाह जारी की गई है। स्वास्थ्य विभाग आदि) को दिव्ली में बचाव अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार, चल रही भीषण गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए हीटवेब के एक्शन प्लान के एक हिस्से के रूप में बचाव अभियान चलाया जाएगा और फुटपाथों, खुले समुदाय के लिए बचाव प्रदान करके बचाया जाएगा। आदेश में कहा गया है, इसलिए, सभी आश्रय प्रबंधन एजेंसियों (एसएमए) को बचाव दल बनाने और आज से ही अपने अधिकार क्षेत्र/क्लस्टर में बचाव अभियान शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।

मर्तृहरि...

अधिकारियों का एक पैनल करेगा जिसमें कांग्रेस नेता के. सुरेश, द्रमुक नेता टीआर बालू, भाजपा के रधा मोहन सिंह और फगन सिंह कुलस्त्रे तथा तुणमूल कांग्रेस नेता सुदीप बंधोपाध्याय शामिल हैं। महताब लोकसभा चुनाव से पहले बीजू जनता दल (बीजद) छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। अठारहवीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा। नवनिर्वाचित सदस्य 24-25 जून को शपथ लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 26 जून को होना है।

^[1] मुर्मू ने बृहस्पतिवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में संवेदनशीलता और समावेशिता की जड़ें मूल्यों के रूप में काफी गहरी समाई हुई हैं और इससे समाज की प्रगति को आंका जा सकता है

^[2] मुर्मू ने बृहस्पतिवार को इस बात पर जोर दिया कि भारत की सभ्यता और संस्कृति में संवेदनशीलता और समावेशिता की जड़ें मूल्यों के रूप में काफी गहरी समाई हुई हैं और इससे समाज की प्रगति को आंका जा सकता है

